door graph
Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

àß-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in

हिंदी दैनिक

गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 10 | अंक : 329 | गुवाहाटी | शनिवार, 29 जून, 2024 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित पेज 2

मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जताया प्रधानमंत्री और गडकरी का आभार पेज 3

पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने शुरू की तैयारियां पेज 5

मीराबाई का लक्ष्य अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ देश को पदक दिलाने का पेज 7

गुवाहाटी विवि मार्कशीट घोटाला

मुख्य आरोपित गिरफ्तार जांच के आदेश

वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से पूछताछ करेगी पुलिस

गुवाहाटी (हि.स.)। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर मार्कशीट घोटाला उजागर हुआ है। यह घोटाला बरपेटा के गणेशलाल चौधरी कॉलेज के एक छात्र से जुड़े जालसाजी मामले की जांच के बाद सामने आया। सभी विश्वविद्यालयों में इसकी जांच करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को गुवाहाटी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से पूछताछ करने भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को बताया कि विश्वविद्यालय के अधिकारी पैसे लेकर छात्रों के अंक बढ़ा रहे थे। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की कम्प्यूटरीकृत मार्कशीट प्रणाली के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोग छात्रों के अंक बढ़ाने के लिए रिश्वत लेते पाए गए हैं। घोटाले के मुख्य -शेष पृष्ठ दो पर

जल्द शुरू होगा कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर परियोजना का काम : सीएम

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि आईआईटी गुवाहाटी के विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार रुके हुए कामाख्या कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस परियोजना से कामाख्या मंदिर परिसर और नीलाचल पहाड़ी के निवासियों को कोई नुकसान नहीं होगा। शर्मा ने आज वार्षिक अंबुवासी मेले के समापन के बाद कामाख्या मंदिर का दौरा किया। वे अपनी पत्नी के साथ कामाख्या मंदिर पहुंचे। उन्होंने देवी से आशीर्वाद लिया और असम के लोगों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मंदिर के दौरे के दौरान शर्मा ने कहा कि टेंडर मिलने के बाद लार्सन एंड टूब्रो को कॉरिडोर के निर्माण की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने इसकी ड्राइंग आईआईटी गुवाहाटी को सौंप दी है। आईआईटी गुवाहाटी से मंजूरी मिलने के बाद हम दो से तीन महीने में काम शुरू कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि कामाख्या कॉरिडोर के निर्माण में

जटिलताएं आने के बाद आईआईटी गुवाहाटी को ड्राइंग की जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। सीएम ने कहा कि आईआईटी गुवाहाटी से मंजूरी मिलने के बाद ही कॉरिडोर का काम शुरू होगा। कॉरिडोर निर्माण के लिए कामाख्या परिसर में स्थित दुकानों को खाली कराना होगा। सीएम ने कहा कि जिन दुकानों को तोड़ा जाना है, उन्हें कॉरिडोर के अंदर ही बनाया जाएगा। इसके अलावा पांच से छह मकानों को भी तोड़ना होगा और उन्हें अन्य स्थानों पर बनाने की व्यवस्था की जाएगी। अंबुवासी मेले पर बोलते हुए शर्मा ने कहा कि अंबुवासी मेले में श्रद्धालुओं के आने की परंपरा पहले नहीं थी। जो लोग अंबुवासी आते हैं, वे यहां ध्यान करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे मेले के बारे में अधिक प्रचार किया जा रहा है, लोगों में यहां आने की उत्सुकता बढ़ रही है। अंबुवासी में भारी भीड़ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह स्थान एक पहाड़ी है, यह वास्तव में इतने लोगों का वजन सहन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अंबुवासी के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण कुछ असुविधाएं हुईं। हम मंदिर के नीचे -शेष पृष्ठ दो पर

कैबिनेट बैठक में विस्तृत मेनू के लिए डीसी को मुख्यमंत्री ने लगाई फटकार

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गुरुवार (27 जून, 2024) को जिले में आयोजित कैबिनेट बैठक में सादा शाकाहारी भोजन परोसने के निर्देशों की अवहेलना करने पर शुक्रवार को नलबाड़ी जिला आयुक्त को कड़ी फटकार लगाई। मुख्यमंत्री शर्मा ने नलबाड़ी की जिला आयुक्त बर्णाली डेका को संबोधित एक औपचारिक पत्र में अपनी नाराजगी व्यक्त की। डीसी नलबाड़ी को संबोधित -शेष पृष्ठ दो पर

नए आपराधिक कानूनों का असमिया अनुवाद न होने से राज्य में अराजकता पैदा होगी : बरठाकुर

गुवाहाटी। असम के वरिष्ठ अधिवक्ता शांतनु बरठाकुर ने असमिया भाषी आबादी पर नए आपराधिक कानूनों के प्रभाव के बारे में चिंता जताई है। 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों के कारण, राज्य के पुलिस बल और कानूनी समुदाय के लिए आवश्यक असमिया अनुवाद उपलब्ध नहीं हैं, जिससे राज्य में अराजकता पैदा हो सकती है, खासकर तब जब लोग पुलिस स्टेशनों पर मामले दर्ज कराते हैं। बरठाकुर ने कहा कि न्यायाधीश और वकील मुख्य रूप से इन कानूनों के मूल अंग्रेजी संस्करणों के साथ काम करेंगे, लेकिन अनुवाद की कमी के कारण लोगों को नए आपराधिक कानूनों को समझने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बरठाकुर ने कहा कि वकीलों और न्यायाधीशों को किसी भी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वे केवल मूल अंग्रेजी संस्करणों पर ही काम करेंगे। सामान्य नागरिकों के लिए कठिनाई उत्पन्न होगी -शेष पृष्ठ दो पर

शर्मा शर्ड3वेब
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

सुप्रभात
बुराई से असहयोग करना मानव का पवित्र कर्तव्य है।
- महात्मा गांधी

प्रशासनिक अखंडता की मांग पर मणिपुर में सड़क पर उतरे हजारों लोग

इंफाल। मणिपुर में शुक्रवार को हजारों लोग रैली में शामिल हुए और राज्य की क्षेत्रीय व प्रशासनिक अखंडता की मांग की। इंफाल के कई समाजिक संगठनों ने साथ मिलकर रैली का आयोजन किया था। इंफाल पश्चिम जिले के थाउ मैदान से शुरू हुई रैली करीब चार किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खुमान लम्पक स्टेडियम में समाप्त हुई। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी, महिलाएं, युवा और गांवों के स्वयंसेवकों -शेष पृष्ठ दो पर

आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 का छत गिरा, एक की मौत, आठ घायल

उड्डयन मंत्री ने दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली (हि.स.)। आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 (डोमेस्टिक) पर शुक्रवार सुबह शेड का बहुत बड़ा हिस्सा गिरने के कारण 9 लोग इसकी चपेट में आ गए। इनमें से रोहिणी (दिल्ली) निवासी आशीष (32) नामक एक कैब चालक की मौत हो गई जबकि अन्य घायलों का इलाज मेदांता अस्पताल (गुरुग्राम) में चल रहा है। दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि दमकल कंट्रोल रूम को 5:30 बजे के आसपास सुबह सूचना मिली थी। मौके पर तुरंत अलग अलग दमकल स्टेशनों से कई गाड़ियां भेजी गईं। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एक-एक करके पहले तीन लोगों -शेष पृष्ठ दो पर

न्यूज गैलरी

विक्रम मिसरी होंगे नए विदेश सचिव

नई दिल्ली (हि.स.)। भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिसरी भारत के नए विदेश सचिव होंगे। उनकी नियुक्ति 15 जुलाई से अमल में आएगी और वह विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। एक सरकारी विज्ञप्ति में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के इस फैसले की जानकारी दी गई है।

नीट पेपर लीक पर सरकार ने लिया सही फैसला : देवेगौड़ा

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। एचडी देवगौड़ा ने विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की और कहा कि जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, सरकार जिम्मेदारी तय नहीं कर सकती। चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए देवगौड़ा ने कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा के आयोजन में कथित अनियमितताओं के कारण लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं। एचडी देवगौड़ा ने कहा कि मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता। सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश देने का सही फैसला लिया है। उन्होंने आगे कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और जब तक यह पूरी -शेष पृष्ठ दो पर

धर्म यानी पूजा नहीं, इसके दो रास्ते...

मुंबई में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत

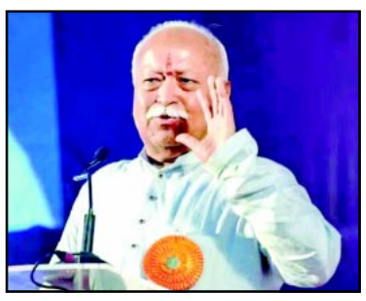

मुंबई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि धर्म के दो मार्ग है, धर्म यानी पूजा नहीं, धर्म समाज को जोड़ कर रखने वाला, अच्छा रखने वाला, उन्नति करने वाला, जो अनुशासन है उसको धर्म कहते हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि धर्म दो मार्ग से होकर गुजरता है। इसमें पहला प्रवृत्ति और दूसरा निवृत्ति है। संघ प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को मुंबई में स्वरस्वामिनी आशा नामक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुशासन को धर्म कहते हैं। धर्म उसे कहते हैं तो जो समाज को जोड़कर और लोगों को अच्छा रखता है। धर्म का मतलब पूजा नहीं होता है। इससे पहले जून की शुरुआत में आरएसएस कार्यकर्ता विकास वर्ग-द्वितीय समापन समारोह में भागवत ने आम चुनाव को लेकर कई बातें कही थीं। नागपुर के कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने कहा था कि ये (चुनाव) देश के प्रजातंत्र में हर 5 साल में होने वाली घटना है। अपने देश के संचालन -शेष पृष्ठ दो पर

सड़क और संसद का अंतर समझें विपक्षी दल : ओम बिरला

नई दिल्ली (हि.स.)। लोकसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को संसद की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित करने से पूर्व हंगामा कर रहे राजनीतिक दलों को कड़ी नसीहत दी। इसके साथ ही उन्होंने हंगामा और नारेबाजी कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में मदद करने का भी अनुरोध किया। ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि आप अपनी जो भी बात रखना चाहते हैं, उसके लिए आपको अवसर दिया जाएगा। पर यहां साफ -शेष पृष्ठ दो पर

तेलंगाना की ग्लास फैक्ट्री में ब्लास्ट, छह की मौत, दर्जनों घायल

हैदराबाद। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक बड़ा विस्फोट हुआ। एक फैक्ट्री में गैस भट्टी फटने से छह श्रमिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। फैक्ट्री में बॉयलर फट गया है। इस कारण यह हादसा हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया है। पुलिस जांच कर रही है कि विस्फोट कैसे हुआ ? पुलिस का कहना है कि घायलों में कुछ की हालत गंभीर है। पुलिस का मानना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। विस्फोट में मजदूरों के शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो गए हैं। बताया गया है कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में 150 लोग मौजूद थे। इस विस्फोट की घटना को -शेष पृष्ठ दो पर

इंदौर : मुस्लिम समुदाय के 35 लोगों ने अपनाया सनातन धर्म

इंदौर (हि.स.)। शहर में मुस्लिम समुदाय के करीब 35 लोगों ने सनातन धर्म अपना लिया है। आयोजन शुक्रवार को स्थानीय खजराना गणेश मंदिर में हुआ। इसके लिए विधि-विधान से खजराना गणेश मंदिर में पूजन-पाठ और हवन किया गया। वैदिक पद्धति से सभी का शुद्धिकरण कराया गया। सनातन धर्म से प्रभावित होकर इन लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया है। जानकारी के अनुसार कानूनन धर्मांतरण के लिए इन लोगों ने इंदौर कलेक्टोरेट में आवेदन दिया था। इसके बाद यह आयोजन किया गया। इनकी लीगल प्रोसीडिंग करने वाले एडवोकेट अनिल नायडू और राहुल राठौर ने इसकी पुष्टि की है। इन सभी लोगों ने विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत के प्रमुख संतोष शर्मा के नेतृत्व में इस्लाम छोड़ कर हिंदू धर्म अपनाया है। इनमें से रोहित पहले हिंदू था। उसने कुछ समय पहले मुस्लिम धर्म अपनाया था। अब उन्होंने घर वापसी की है। विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत के प्रमुख संतोष शर्मा ने कहा कि धर्मांतरण कर रहे सभी लोगों की -शेष पृष्ठ दो पर

रास में सभापति और नेता प्रतिपक्ष में तकरार, धनखड़ नाराज

नई दिल्ली (हि.स.)। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के व्यवहार पर तीखी नाराजगी प्रकट की। धनखड़ ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ और मर्यादित पद होता है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को आसन के सामने वेल में आकर नारेबाजी नहीं करनी चाहिए थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि वे सदन में सभापति जगदीप धनखड़ का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते थे, इसलिए वे वेल के अंदर गए। खड़गे ने इस स्थिति के लिए राज्यसभा के सभापति को ही दोषी ठहराते हुए -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivling, Nandi etc. **ARTCLE WORLD,** S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, **Ph. : 94350-48866, 94018-06952**

नगांव में हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार

नगांव (हिंस)। नगांव में हेरोइन के साथ आज एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नगांव थाना के सब इंस्पेक्टर रूपज्योति हजारिका के नेतृत्व में शहर के हैबरगांव से नगांव पुलिस की एक टीम ने संदिग्ध हेरोइन से भरी एक साबुनदानी बरामद किया। बरामद हेरोइन का वजन 10.62 ग्राम है। आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए गिरफ्तार कर लिया गया।

नीट को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा

लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित

नई दिल्ली। आज सुबह जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई नीट मामले को लेकर हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा में विपक्ष मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में हुई धांधली पर चर्चा की मांग की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चर्चा करने को कहा। हालांकि, विपक्ष इस मांग पर अड़ा रहा कि सदन में पहले नीट पर चर्चा होनी चाहिए। मामला शांत न होता देख सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से जुड़े मामलों पर चर्चा की अपनी मांग जारी रखी। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। बिरला ने कहा कि संसद के कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन करना होता है। समितियां गठित करनी होती हैं। इस पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि छात्रों को इसकी जानकारी नहीं है। वे केवल न्याय की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके के सदस्यों ने हंगामे के बीच रिजिजू ने कहा कि यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लेने से पहले विपक्ष किसी मुद्दे पर चर्चा की मांग करता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष को आश्वासन देता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आप जिस भी मुद्दे को उठाएंगे, हम उसका जवाब देंगे। हालांकि, सदस्यों की नारेबाजी के बीच बिरला ने कहा कि लोगों ने इस सदन में सदस्यों को इसलिए चुना है ताकि वे मुद्दों को उठा सकें और उन पर चर्चा कर सकें। कार्यवाही बाधित करने के लिए नहीं चुना है। उन्होंने विपक्ष से सवाल करते हुए कहा कि सड़क पर प्रदर्शन और सदन के अंदर प्रदर्शन के बीच अंतर है। आप नहीं चाहते कि सदन चले? आप धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नीट पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं? सदन में हंगामा जारी रहने पर बिरला ने कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं, हंगामे के बीच तृणमूल कांग्रेस के सदस्य एस के नुरुल इस्लाम ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। किरेन रिजिजू ने बाद में पत्रकारों से कहा कि सरकार की तरफ से हमने साफ कर दिया है कि जो भी मुद्दा उठाया जाएगा, हम उस पर विस्तृत जानकारी देंगे। हम सदस्यों को एक बार फिर आश्वस्त करते हैं कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन सदन की कार्यवाही को बाधित करके कांग्रेस पार्टी द्वारा सदन की कार्यवाही नहीं चलने देने की जो प्रवृत्ति अपनाई जा रही है, वह सही नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं अपील करता हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए।

धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज

नई दिल्ली (हि.स.)। भारत ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि मानवाधिकार के नाम पर दूसरे देश की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट-2023 पर सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट पहले की ही तरह पक्षपातपूर्ण है तथा वोटबैंक की राजनीति से प्रेरित है। भारत इस रिपोर्ट को अस्वीकार करता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस रिपोर्ट को जारी करते हुए भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून और अल्पसंख्यकों के मकानों और उपासनों स्थलों को निशाना बनाया जाना और नफरती बयानबाजी चिंता का विषय है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस रिपोर्ट में गलतबयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है। इसमें सूचना हासिल करने के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित स्रोतों का सहारा लिया गया है तथा इसके निष्कर्ष पहले से ही तय कर लिये गए हैं। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट भारत के सामाजिक ताने-बाने की अज्ञानता पर आधारित है। इसमें भारत के कानून की वैधता तथा विधायिका के अधिकारों पर भी सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट भारत की न्यायपालिका के फैसलों को भी चुनौती देती है।

ड्रग्स समेत एक गिरफ्तार

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी की भरालुमुख पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी मामले में शामिल एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र इलाके में चलाए गए अभियान के दौरान 45 प्लास्टिक की छोटे-छोटे सीसी में भरकर रखी गई 59.79 ग्राम हेरोइन समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान हाफिजुर रहमान (24) के रूप में की गई है। पुलिस इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक प्राथमिक की दर्ज कर गिरफ्तार आरोपी से सघन पूछताछ कर रही है।

छह महीने बाद जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन, मिली जमानत

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दिए जाने के बाद रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए। सोरेन जब पत्नी कल्पना सोरेन के साथ जेल से बाहर निकले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के बीच उनका स्वागत किया। मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने सोरेन, आईएएस अधिकारी और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, भानु प्रताप प्रसाद और अन्य सहित 25 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। अपनी गिरफ्तारी के समय, सोरेन ने अपने खिलाफ जमीन हड़पने के आरोपों से दृढ़ता से इनकार किया था और कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला थोपा था। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ ही मिनट बाद उन्हें 31 जनवरी को रांची राजभवन से गिरफ्तार कर लिया गया था। 22 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने सोरेन और अन्य के खिलाफ कथित भूमि हड़पने से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत रांची में छापे के बाद 1 करोड़ रुपए नकद और 100 जिंदा गोलियां जब्त कीं। सोरेन को जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर कहा कि वह विकास से *बहुत खुश* हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि एक महत्वपूर्ण आदिवासी नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक मामले के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन आज उन्हें माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है! मैं इस महान विकास से बहुत खुश हूं और मुझे यकीन है कि वह अपनी सार्वजनिक गतिविधियां तुरंत शुरू कर देंगे।

आसनसोल में संघ कार्यालय पहुंची पुलिस, जमीन के दस्तावेज मांगे

कोलकाता (हि.स.)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद राज्य की पुलिस अवैध निर्माण के खिलाफ अति सक्रिय हो गई है। राज्य भर में सड़कों पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों के अवैध कब्जे की अनदेखीकर आसनसोल में पुलिस सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के दफ्तर में जा पहुंची। पुलिस, आसनसोल नगर पालिका और भूमि राजस्व अधिकारियों की एक टीम जमीन के दस्तावेज देखने के लिए आसनसोल के जेसी बोस लेन, वार्ड नंबर 21 स्थित संघ कार्यालय पहुंचे। पुलिस के कार्यालय पहुंचने की सूचना पाकर स्वयंसेवक भी पहुंच गए। संघ के वकील पीयूषकांति गोस्वामी ने शुक्रवार को कहा कि किसी ने शिकायत की है। इसीलिए वे आए थे। लेकिन हमें नहीं पता कि शिकायत क्या है। हमें सूचित नहीं किया गया। उन्होंने दस्तावेज मांगे। हमने बताया है कि हमारे पास सभी दस्तावेज हैं लेकिन यहां नहीं कोलकाता के केशव भवन में हैं। लाने के लिए 15 दिन का समय दें। वे सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे भी नोटिस देंगे। आसनसोल पुलिस आयुक्तालय के अतिरिक्त उपायुक्त सुब्रत देबनाथ भी संघ कार्यालय का दौरा करने वाले सरकारी अधिकारियों में से थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक शिकायत मिली है। उसके आधार पर कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं। संघ ओर से सकारात्मक सहयोग मिला है। उल्लेखनीय है कि नवान्न में एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ममता ने कहा था कि मलय (मंत्री मलय घटक) मुझे बता रहे थे कि एक राजनीतिक दल ने आसनसोल में एक तालाब भरकर तीन मंजिला घर बनाया है। इसे तोड़ा क्यों नहीं जा रहा? पुलिस को बार-बार बताया गया, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।

पूसीरे के जीएम ने किया अग्रिम पंक्ति के संरक्षा कर्मचारियों से विचार-विमर्श

गुवाहाटी (हिंस)। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने आज पूसीरे मुख्यालय, मालीगांव में अग्रिम पंक्ति के संरक्षा कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श के दौरान, पूसीरे के सभी विभागों के प्रधान भी उपस्थित थे। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची डे ने बताया कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के सभी पांच मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस सत्र का उद्देश्य सुरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ यात्रियों के लिए एक विश्वसनीय यात्रा का अनुभव प्रदान करना था। इस दौरान सभी सुरक्षा उपायों और सुरक्षित ट्रेन परिचालन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर भी विचार-विमर्श किया गया।

पृष्ठ एक का शेष

मुख्य आरोपित गिरफ्तार ...

आरोपित को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस प्रकार के छह मामले अब तक सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम पुलिस और सीआईडी दोनों संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है। जांच में विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग प्रणाली में भ्रष्टाचार के विशाल नेटवर्क का पता चला। यह घोटाला तब सामने आया जब कॉलेज के अधिकारियों को छठे वर्ष के स्नातक छात्र अजीजुल हक की मार्कशीट में अंकों की जालसाजी का पता चला। बरपेटा पुलिस ने अजीजुल हक को गिरफ्तार करने के बजाय घटना को छिपाने की कोशिश की। मीडिया में खबरें आने के बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस से जांच करने को कहा। इसके बाद बरपेटा पुलिस और सीआईडी की जांच में इस प्रकार के घोटालों के कई मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के मामले अन्य विश्वविद्यालयों में भी हो सकते हैं।

जल्द शुरू होगा ...

4,000 लोगों के लिए व्यवस्था करने की योजना बना रहे हैं। कामाख्या मंदिर एक्सेस कॉरिडोर प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर विकास पहल (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल, पीएम-देवीन) के तहत 402 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली परियोजना है। घोषित परियोजना के तहत कामाख्या मंदिर और उसके परिसर का आधुनिकीकरण किया जाना है। असम सरकार के लोक निर्माण विभाग (आवास और राजमार्ग) को इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अवधारणा नियोजन की जिम्मेदारी दी गई थी। मां कामाख्या ऑफिस एक्सेस कॉरिडोर परियोजना की योजना में कामाख्या मंदिर के पास कई बहुमंजिला इमारतें बनाई जाएंगी। इनमें क्लॉक रूम, टिकट काउंटर, सूचना केंद्र, स्मारिका दुकानें और अन्य शामिल होंगे। दूसरी ओर मल्टी यूटिलिटी ब्लॉक में वीवीआईपी, ट्रस्ट कार्यालय, भोजनालय, रसोई, रेस्तरां, पुस्तकालय, वीवीआईपी लॉन्च और छत पर वीवीआईपी सेवाओं के लिए प्रवेश बिंदु होंगे। तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था (3 मंजिलें जहां 14,000 लोग रह सकते हैं), प्रसाद ब्लॉक में दुकानें, सेवा ब्लॉक में सुरक्षा गार्ड और स्वयंसेवकों की व्यवस्था होगी। ये इमारतें कामाख्या मंदिर और आस-पास के मंदिरों के आसपास बनाई जाएंगी। उल्लेखनीय है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 28 नवंबर 2023 को आमंत्रित की गई निविदा के अनुसार ये इमारतें बेसमेंट सहित चार मंजिला होंगी। दूसरी ओर कामाख्या कॉरिडोर के निर्माण को लेकर भी विवाद हो गया है। मामला पहले ही कोर्ट पहुंच चुका है। 19 जून को कामाख्या मंदिर कॉरिडोर मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने हलफनामा दाखिल कर आईआईटी की विशेषज्ञ रिपोर्ट आने तक कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का निर्माण शुरू न करने की बात कही थी। स्मरणीय है कि कामाख्या कॉरिडोर के निर्माण को चुनौती देते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं और जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। कामाख्या मंदिर के पुजारी नवज्योति शर्मा द्वारा दायर याचिका में प्रस्तावित कॉरिडोर के निर्माण के कारण कामाख्या मंदिर पर मंडरा रहे खतरे के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। वहीं दूसरी ओर कामाख्या मंदिर से जुड़े पुजारी समुदाय ने नीलाचल पहाड़ियों के जल विज्ञान और भूगर्भीय अध्ययन के बिना इस परियोजना के क्रियान्वयन पर चिंता जताई है। उनके अनुसार, कामाख्या मंदिर में परियोजना निर्माण कार्य से उसके भूगर्भीय पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हाल ही में हुई सुनवाई में असम सरकार के मुख्य सचिव रवि कोटा ने न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर कहा कि आईआईटी गुवाहाटी को मामले का अध्ययन करने के लिए कहा गया है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि सरकार संस्थान द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कॉरिडोर पर काम शुरू करेगी।

कैबिनेट बैठक में विस्तृत ...

पत्र (सं.सीएमओ.1/2024/4560) में कहा गया है कि 27/06/2024 को नलबाड़ी में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान सादा शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करने के लिए इस कार्यालय से बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद, आपने निर्देशों का पालन नहीं किया है। सीएम शर्मा ने आगे जोर देते हुए कहा कि मैं आपकी ओर से इस तरह की कार्रवाई के लिए अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करता हूं। इसके बाद, ऐसे निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि असम मंत्रिमंडल मई 2021 से राज्य में शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के गठन के बाद से विभिन्न जिलों में बैठकें कर रहा है। मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक दक्षता में सुधार और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को विकेंद्रीकृत करने के सरकार के प्रयासों के तहत यह निर्णय लिया। अन्य दिशा-निर्देशों के अलावा, सीएम को गामोछा (दुपट्टा)/फूलों के गुलदस्ते से सम्मानित करने से सख्ती से बचना चाहिए और कैबिनेट के दौरान सीएम को कोई उपहार नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही, कैबिनेट ने बैठक के दौरान शाकाहारी मेनू, स्थानीय आदिवासी शैली का मेनू और मिट्टी के प्यालों में चाय परोसने का भी निर्देश दिया है।

नए आपराधिक कानूनों ...

जो अंग्रेजी या नए आपराधिक कानूनों में शामिल जटिल शब्दावली को नहीं समझते हैं। हालांकि उन्हें यकीन नहीं है कि कानून का हिंदी में अनुवाद किया गया है या नहीं, लेकिन उन्होंने पुष्टि की कि अन्य राज्यों में अभी केवल अंग्रेजी संस्करण ही उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि असमिया अनुवाद कब उपलब्ध होगा। नए कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में बोलते हुए बरठाकुर ने एक *अराजक* संक्रमण काल की भविष्यवाणी की। उन्होंने बताया कि धाराएं अलग-अलग होंगी और कुछ मामलों में भाषा भी कठिन होगी। वकीलों और न्यायाधीशों पर अलग-अलग कानूनों की व्याख्या करने वाले मामलों का बोझ पड़ेगा। उन्होंने पुलिस हिरासत जैसी स्थितियों में उत्पन्न होने वाले भ्रम की ओर ध्यान दिलाया, जहां मामला कब शुरू किया गया था, इस पर निर्भर करते हुए नए और पुराने दोनों कानूनों का संदर्भ लेना पड़ सकता है, जिससे शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों को असुविधा हो सकती है। बरठाकुर ने आगे कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब वकीलों को 1 जुलाई से पहले के मामलों के लिए तथा नए कानून लागू होने के बाद के मामलों के लिए नए और पुराने दोनों आपराधिक कानूनों का संदर्भ लेना होगा।

प्रशासनिक अखंडता की...

ने रैली में हिस्सा लिया। लोगों ने पड़ोसी देश म्यांमार से अवैध तौर पर घुसे प्रवासियों के खिलाफ नारे लगाए। रैली में लोगों ने *भारत के मूलनिवासी और नागरिकों को बचाओ, अलग प्रशासन नहीं* और *मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बचाओ* जैसे नारे लगाए।

आईजीआई एयरपोर्ट के...

को निकाला गया। उसके बाद और लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। मौके पर असिस्टेंट डिविजनल ऑफीसर रविनाथ को भेजा गया था। दमकल की टीम के अलावा पीसीआर कैट्स टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। इस मामले में पुलिस की तरफ से जानकारी देते हुए डीसीपी एयरपोर्ट उषा रंगनानी ने बताया कि यह हादसा भारी बारिश के कारण टर्मिनल 1 डोमेस्टिक एयरपोर्ट के बाहरी हिस्से में हुआ। प्रस्थान गेट नंबर 1 से 2 के बीच शेड का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। चार गाड़ियां शेड के नीचे दब गईं और कई लोग इसमें चपेट में आ गए थे। इनमें से एक शख्स की मौत हो गई। मौके पर दिल्ली पुलिस के साथ दमकल, सीआईएसएफ और एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंच कर रेस्क्यू कार्य को अंजाम दिया। इस हादसे के बाद वहां पर इकट्ठा हुए लोगों को धीरे-धीरे हटा करके टर्मिनल 2 और 3 की तरफ भेजा गया और शेड के गिरे हुए मलबे और क्षतिग्रस्त गाड़ियों को वहां से हटाया गया। मौके से मिली जानकारी के अनुसार जो गाड़ियां शेड की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुई हैं, वो सभी कैब हैं, जो यात्रियों को की आवाजाही के लिए काम करती हैं। सुबह जब अचानक भर भराकर शेड नीचे गिरा तो वहां पर भगदड़ मच गई। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि यहां पर क्या हो गया। जिस शख्स की मौत हुई है, वह एक कैब की ड्राइविंग सीट पर ही फंसा रह गया। वह निकल नहीं पाया। बाद में जब निकाला गया तो डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल वन पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 3- 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। नायडू ने बताया कि यह वह बिल्डिंग नहीं है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बिल्डिंग 2009 में बनी थी। इसमें किसकी लापरवाही है, इसकी जांच की जाएगी। लोगों ने उन्हें जानकारी दी कि जो हिस्सा गिरा है, वह देखने में डैमेज लग रहा था। इस पर उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा। फिलहाल, टर्मिनल 1 को पूरी तरह खाली करा दिया गया है। जांच पड़ताल के बाद कल से इसे शुरू किया जा सकता है। मौके पर पहुंचे असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर रविंद्र ने बताया कि जो शख्स गाड़ी के अंदर फंस गया था, उसे निकालने में 20 मिनट लगा। क्योंकि लोहे का खंबा गाड़ी के ऊपर ही आकर गिरा था। उसे सावधानी से हटाना जरूरी था, नहीं तो और भी कुछ डैमेज हो सकता था। फायर ब्रिगेड की हाइड्रा गाड़ी से उस पिलर को थोड़ा ऊपर उठाया गया और फिर उस शख्स को गाड़ी से निकालकर तुरंत अस्पताल भेजा गया। एयरपोर्ट पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वर्ल्ड क्लास इस हवाई अड्डे पर पहली बारिश में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। शेड का बहुत बड़ा हिस्सा अचानक नीचे गिर गया। इसके पीछे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस लोहे के पिलर पर यह शेड खड़ा था, उनमें से कोई पिलर जमीन के खिसकने की वजह से अनबेलेंस हुआ है। इसके बाद यह स्ट्रक्चर नीचे गिरा है। एयरपोर्ट हादसे में जिस शख्स की मौत हुई है, उसकी पहचान 32 साल के आशीष के रूप में हुई है। वह रोहिणी के फेज वन स्थिति विजय विहार शनि बाजार का रहने वाला था। यहां वह परिवार की साथ रहता था। एयरपोर्ट हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान साहिल, योगेश्वर, संतोष कुमार यादव, शुभम शाह, ध्रुव, दशरथ, पार्थ और अरविंद के रूप में हुई है। ये सभी दिल्ली, बिहार और गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनका इलाज गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल में किया जा रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। पूरी तरीके से जांच के बाद ही टर्मिनल-1 को फिर से शुरू किया जाएगा। उड़ानों के संचालन को टर्मिनल-2 और टर्मिनल-3 पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा, सरकार की तरफ से मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का एलान किया है। वहीं, घायलों को तीन लाख रुपए मदद देने की घोषणा की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि जिस जगह हादसा हुआ, वो 2009 में बना था। उधर सरकार के सूत्रों ने बताया कि टर्मिनल 1 पर ढही छत का निर्माण 2008-09 के दौरान किया गया था और जीएमआर ने निजी ठेकेदारों को इस काम का ठेका दिया था। मंत्री का कहना है जांच के बाद घटना के तकनीकी कारणों और अन्य पहलुओं का पता चल सकेगा। एयरपोर्ट ऑपरेटर डायल (एओडी) ढांचे की जांच करेगा। साथ ही डीजीसीए निरीक्षण की निगरानी करेगा और वे एक रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश भर के हवाई अड्डों पर सभी समान संरचनाओं की गहन जांच की जाएगी।

नीट पेपर लीक पर ...

नहीं हो जाती, सरकार जिम्मेदारी तय नहीं कर सकती। देवगौड़ा ने विपक्षी सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हालांकि, सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। वहीं धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने वाले भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गौड़ा जैसे वरिष्ठ सदस्य की तरफ से आदेश की अपील के बावजूद विपक्ष अपना विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी जारी रखे हुए है। बता दें कि राहुल गांधी, सहित कई कांग्रेस सांसद ने सदन में नीट पर चर्चा की मांग की। वहीं पार्टी की राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेता भी नीट के मुद्दे पर सदन के वेल में विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। इसी दौरान वह चक्कर आने के बाद गिर पड़ीं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

धर्म यानी पूजा ...

के लिए कुछ निर्धारण करने वाला महत्वपूर्ण प्रसंग है। मगर उस पर ही चर्चा करते रहें, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। समाज ने अपना मत दे दिया है। उसके हिसाब से सब कुछ होगा। क्यों और कैसे हुआ? हम संघ के लोग इसमें नहीं पड़ते। मोहन भागवत ने आगे कहा था कि संसद क्यों है और उसमें दो पक्ष क्यों हैं? ये इसलिए हैं क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सहमति बने इसलिए संसद बनती है। चुनाव में जिस तरह से एक-दूसरे को लताड़ा गया और लोग बटेंगे, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। बेवजह संघ जैसे संगठन को घसीटा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर चुनाव में झूठी बातें परोसी गई।

सड़क और संसद का ...

दिख रहा है कि आप योजनाबद्ध तरीके (प्लांड वे) में संसद की कार्यवाही को चलने नहीं देना चाहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि चुनावों के बाद यह संसद का पहला सत्र है। लोग आपके कार्यकलाप देख रहे हैं। जनता ने आपको इसलिए चुनकर भेजा है ताकि आपकी उनकी बात यहां रख सकें लेकिन आप जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे लगता है कि आप सड़क और संसद के बीच का अंतर नहीं समझते हैं। ओम बिरला ने कहा कि संसदीय व्यवस्था और परम्परा के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद केवल उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर ही चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में नीट परीक्षा का मुद्दा भी उठाया था। आप चर्चा में भाग लेकर उस पर अपनी बात रख सकते हैं। नियम को दरकिनार कर बहस कराने की मांग करने और हंगामा करने की नीयत पर लोकसभा अध्यक्ष ने तीखा कटाक्ष भी किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसदीय परम्परा का हवाला देते हुए इसे देश के सर्वोच्च पद के प्रति असम्मान बताते हुए विपक्षी दलों से कहा कि वे धन्यवाद प्रस्ताव में बात रखते हुए किसी भी विषय पर अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। सरकार हर विषय पर जवाब देगी। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि पिछली लोकसभा में उन्हें अनेक बार सत्र संचालन करने का अवसर मिलता था। उन्होंने पाया कि विपक्षी दल एक तरफ तो सदन में अपनी बात रखने के लिए समय की मांग करते हैं। इसके विपरीत जब अवसर दिया जाता है तो कोई न कोई शर्त रखकर हंगामा और नारेबाजी करने लगते हैं। कुछ सांसदों को लगता है कि गंभीर चर्चा करने की बजाय हल्ला हंगामा करने से उन्हें ज्यादा प्रसिद्धि मिलेगी। यह सोच संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। इस बार विपक्ष पहले से कुछ अधिक संख्या बल में जीतकर आया है। उन्हें अपनी ताकत लोगों की बात रखकर दिखानी चाहिए न कि संसद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाकर। संसदीय कार्यमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष की नसीहत और स्पष्ट रूप से नीट पर बहस को तैयार होने की बात कहने के बावजूद विपक्षी दलों का हंगामा बताता है कि वे बहस नहीं, विवाद में विश्वास रखते हैं।

रास में सभापति और ...

कहा कि वे प्रतिपक्ष की अनदेखी कर रहे हैं। दरअसल, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के शुक्रवार को राज्यसभा की वेल में आने पर चिंता जताते हुए कहा था कि आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागदार हो गया है कि विपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं पीड़ित और अचंभित हूं कि आज संसद की परंपरा इतनी गिर जाएगी, प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे। सदन के बाहर खड़गे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे राज्यसभा के सभापति का ध्यान अपनी ओर दिलाना चाहते थे लेकिन वे केवल सत्ता पक्ष की ओर देख रहे थे। खड़गे ने यह भी कहा कि जब वे नियमानुसार उनका ध्यान आकर्षित करा रहे थे तो राज्यसभा के सभापति को उनकी ओर देखना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपमानित करने के लिए जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर दिया। ऐसी स्थिति में मुझे या तो अंदर जाना होगा या बहुत जोर से चिल्लाना होगा। खड़गे ने आगे कहा कि वे निश्चित रूप से कह रहे हैं कि यह सभापति साहब की गलती है। मैं कहता हूं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और इस राज्यसभा की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इतने बड़े घोटाले हुए हैं। नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, लाखों बच्चे चिंतित हैं। इसलिए लोगों की समस्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने एक विशेष चर्चा के लिए कहा कि हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। हम केवल छात्रों के मुद्दों को उठाना चाहते थे लेकिन उन्होंने इसका मौका नहीं दिया, इस पर ध्यान ही नहीं दिया और इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ा।

इंदौर : मुस्लिम समुदाय...

घर वापसी हो रही है। इस्लाम छोड़ इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है। मंदिर में हिंदू धर्म अपनाने के लिए अभी और भी लोग पहुंच रहे हैं। ये सभी इंदौर और आसपास के इलाकों में रहने वाले हैं। शर्मा ने बताया कि सभी के बारे में कलेक्टोरेट कार्यालय में शपथ पत्र दे दिया है। इनमें इंदौर, देवास, सांवेर और अन्य जिलों के लोग शामिल हैं। सबसे ज्यादा 12-13 लोग इंदौर के हैं। महिला-पुरुषों की संख्या बराबर है। सभी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कैडर से प्रभावित होकर माना है कि सनातन से श्रेष्ठकुछ नहीं हैं। उन्हें अपने धर्म के कट्टरपंथी कानून का पालन करने में दिक्कत आ रही थी। खासकर हलाला और तीन तलाक, जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। सनातन में कोई कट्टरपंथी नहीं है। सनातन धर्म अपनाने के बाद इन लोगों का नया नामकरण किया गया है। इनमें जमीन बी (58) अब जमना बाई, नीलोफर शेख (34) अब निकिता, अक्षा शेख (34) अब आकांक्षा, रज्जाक अब रोहित, अंजुम शाह अब आरती, अबरार अब अभिषेक, मुबारिक अब मनीष, रहमान अब हीरालाल, रईस अब राजू, रईस खान अब अर्पित, सुरया बी अब पूजा, मेहरु बी अब ममता, कालू खां अब करुलाल, रुकैया अब रुक्मणि, जरीना बी अब जानवी, जाकिर अब राहुल, रजिया अब रानी, शमीम शाह अब शानू, राबिया बी अब लाली, सलमा बी अब सरिता, रफीक मोहम्मद अब राहुल, राबिया बी अब रंजना, अल्फिया अब आशु के नाम से पहचानी जाएंगी।

तेलंगाना की ग्लास...

लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को अलर्ट किया है। दुर्घटनास्थल पर कलेक्टर को दुर्घटना में घायल हुए लोगों के बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि राजस्व, पुलिस, अग्निशमन विभाग, श्रम, उद्योग और चिकित्सा दल घटनास्थल पर रहें और समन्वय बनाकर राहत और बचाव कार्य तेज गति से करें। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल होने के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बॉयलर फटने से मजदूरों के शव इधर-उधर बिखर गए और फैक्ट्री में भयंकर आग लगी हुई है। इस हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। आग में कुछ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का मानना है कि हादसा बॉयलर फटने से हुआ है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस हादसे में ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की मौत हुई है, हालांकि पुलिस ने अभी तक मृतकों के नामों का खुलासा नहीं किया है। मृतकों के शवों की पहचान की जा रही है।

अगरतला स्टेशन पर दो बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार

अगरतला (हिंस)। अगरतला स्टेशन पर दो बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। दोनों बांग्लादेशी महिलाएं अवैध रूप से त्रिपुरा में प्रवेश करने के बाद कर्नाटक जाने की तैयारी कर रही थी। अगरतला रेलवे पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि तलाशी के दौरान उनके बांग्लादेशी होने का प्रमाण सामने आया। दोनों अगरतला रेलवे स्टेशन पर कर्नाटक जाने के लिए पहुंची थीं। उन्हें गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है।

पिस्तौल के साथ एक गिरफ्तार

नगांव (हिंस)। नगांव में पिस्तौल के साथ एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आज बताया कि डीएसपी (पी) संदीपन गर्ग के नेतृत्व में जुरिया थाना से नगांव पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर एक 0.22 कैलिबर की वियतनाम में निर्मित पिस्तौल और 4 राउंड जिंदा गोला-बारूद बरामद किया।

मणिपुर में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद

इंफाल (हिंस)। मणिपुर में सुरक्षा बलों द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। इन अभियानों में हथियार और गोला बारूद की बरामदगी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले में राज्य के अलग-अलग स्थानों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद संयुक्त सुरक्षा बलों के अभियान में बरामद किये गये। मणिपुर पुलिस ने आज बताया कि पहाड़ी और घाटी जिलों के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन चलाया गया। इस दौरान काकचिंग जिले के सिंगटॉम गांव से दो एचई-36 ग्रेनेड, डेटोनेटर और फ्यूज, एक बीपी जैकेट, एक कॉम्बैट टी-शर्ट और एक प्लास्टिक बैग बरामद किया गया। वहीं, एक अन्य तलाशी अभियान में चुराचांदपुर जिले के चिंगफेई गांव और हेइचांगलोक से तीन इम्प्रोवाइज (तीन पंप) बरामद किए गए। इनके अलावा एक अलग तलाशी अभियान में इम्फाल पश्चिम के नाओरेम लेईकाई पेना खोंगबा इलाके से दो पिस्तौल, 12 जिंदा राउंड गोला बारूद, एक डेटोनेटर रहित हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया। सुरक्षा बलों द्वारा पूरे राज्य में छापामारी अभियान चलाया जा रहा है।

मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जताया प्रधानमंत्री और गडकरी का आभार

इंफाल (हिंस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन आदि मामलों के मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और एनएचआईडीसीएल की समर्पित टीम को राज्य में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में उनकी प्रतिबद्धता और समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ज्ञात हो कि महत्वपूर्ण मार्ग की उपेक्षा की 70 सालों से की गई। इस अवधि का अंत करते हुए तामेंगलोंग-तौसेम-लिसांग-माहुर रोड (एनएच-137) के लिए पक्की सड़कों के साथ 2-लेन सड़क का निर्माण, डायलोंग गांव के पास 10 किलोमीटर

से बराक नदी के पास 31 किलोमीटर तक यह सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इम्फाल-जिरीबाम राजमार्ग, मकरू, इरंग और बराक नदी पर महत्वपूर्ण पुल भी पिछले कुछ वर्षों में पूरे हो गए हैं।

तस्करी कर लाई गई नाबालिग को बचाया

धुबड़ी (हिंस)। धुबड़ी से तस्करी कर लाई गई नाबालिग को आज गुवाहाटी में मुक्त करा लिया गया। असम पुलिस ने आज सोशल मीडिया के जरिए बताया कि धुबड़ी से तस्करी कर लाई गई और जबरन मजदूरी करने वाली एक नाबालिग लड़की को, एसएमआरसी के समय पर हस्तक्षेप और कामरूप (मेट्रो) बाल श्रम टास्क फोर्स, श्रम विभाग और गुवाहाटी पुलिस के साथ समन्वय से गुवाहाटी में बचा लिया गया। पुलिस तस्कर को पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रही है।

राज्यपाल ने स्कूली बच्चों के साथ अपना 71वां जन्मदिन मनाया

इटानगर (हिंस)। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक, (सेवानिवृत्त) ने आज हियरिंग एंड डोनयी पोलो मिशन विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल चिम्पू का दौरा किया। राज्य की प्रथम महिला अनघा परनायक के साथ आए राज्यपाल ने संस्थान के बच्चों और अधिकारियों के साथ अपना 71वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर डोनी पोलो मिशन के अध्यक्ष गेगोंग अपांग, पूर्व मुख्यमंत्री भी अन्य लोगों के साथ उपस्थित थे। राज्यपाल और राज्य की प्रथम महिला ने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताया और विशेष शिक्षकों के माध्यम से उनके साथ बातचीत की। बच्चों ने उनको अपनी शुभकामनाएं दीं। छात्रों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने *अरुणाचल प्रदेश का चमकता सितारे* कहा। राज्यपाल ने छात्रों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए हर संभव अवसर प्रदान करने में राज्य सरकार और राजभवन से सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डोनी पोलो मिशन स्कूल ने उन्हें प्रशिक्षित किया और उनकी देखभाल की, उसमें बच्चों ने सीखने की भावना और मानवीय सहनशक्ति का प्रदर्शन किया। राज्यपाल ने *बाल दिवस* और उसमें होने वाले अन्य समारोहों के अवसर पर छात्रों को राजभवन में आमंत्रित करने का वादा किया। उन्होंने श्रवण और दृश्य चुनौतियों वाले छात्रों के लिए सीखने, प्रशिक्षण और चिकित्सा के लिए बेहतर उपकरण और अध्ययन सामग्री का भी वादा किया।

जेसीआई, रंगिया रॉयल्स ने मंदिर में लगाई स्वच्छ पानी की मशीन

रंगिया (विभास)। रंगिया की अग्रणी स्वेच्छासेवी संस्था जेसीआई रंगिया रॉयल्स द्वारा शुक्रवार को रंगिया के तिनाली स्थित श्री श्री हनुमान मंदिर प्रांगण में स्वच्छ पानी की मशीन (एक्वागार्ड) लगवाकर इसे लोगों की सेवा में अर्पित किया। शाखाध्यक्ष शोभा अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित इंस्टालेशन कार्यक्रम का शुभारंभ मंदिर के पुजारी जिकेश मिश्रा द्वारा मंत्रोच्चार के साथ फीता काटकर किया गया। इस मौके पर शाखा सचिव गरिमा सिकारिया, कोषाध्यक्ष प्रिंस सराफ सहित शाखा के पदाधिकारी पुनीत क्याल, अंकुर अग्रवाल, अंकुर लुंडिया और प्रियल क्याल भी उपस्थित रहे।

रंगिया : नागरिक मंच ने विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए महकमाधिपति को सौंपा ज्ञापन

रंगिया (निसं)। रंगिया के नागरिक मंच के एक समुह ने महकमाधिपति से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मुख्यत: प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं पर चर्चा करने के लिए रंगिया के महकमाधिपति से मुलाकात की। समुह ने सरकार से रंगिया के सरकारी चिकित्सा केंद्रों पर सांप काटने का इलाज तुरंत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। समुह ने प्रशासन को रंगिया मे 4.52 करोड़ रुपए की लागत से 47 बिस्तरों वाले आईसीयू अस्पताल का आधिकारिक उद्घाटन 26 मार्च, 2023 को स्थानीय विधायक भवेश कलिता की उपस्थिति में होने के बारे मे अवगत कराया। उसी आदर्श अस्पताल में एक्स-रे मशीन भी तब से अप्रयुक्त है। इस बीच, अस्पताल

के अंदर डायलिसिस सेंटर के लिए लाई गई तीन मशीनें मशीनों को स्थापित करने के लिए जगह की कमी के कारण पिछले चार महीनों से गोदाम में रखे जाने पर क्षोभ प्रकट किया। उन्होंने रंगिया सब-डिवीजन सिविल अस्पताल के अभी भी 100 बिस्तरों के बजाए केवल 30 बिस्तरों के साथ चलने का मुद्दा भी उठाया। क्षेत्र के निवासियों ने मांग की कि अस्पताल में यांत्रिक विफलताओं और चिकित्सा कर्मचारियों की कमी को पूरा करके जल्द से जल्द इसे और अधिक कार्यात्मक बनाया जाए की मांग की। इसी बीच, आदर्श अस्पताल के मुद्दे को लेकर उसी दिन युवा कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी महकमाधिपति से मिलने की जानकारी मिली है।

सांप के काटने से किशोर की मौत

धुबड़ी (हिंस)। धुबड़ी मेडिकल कॉलेज में आज उस समय उत्तेजक स्थिति उत्पन्न हो गई, जब एक डॉक्टर पर सर्पदंश से पीड़ित के ईलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया। सर्पदंश से ग्रस्त मोफिजुल हक नामक एक किशोर की अस्पताल में भर्ती होने के कुछ ही देर बाद मौत हो गई। मृतक के भाई ने आज मीडिया को बताया कि मृतक मोफिजुल को रात में हाईवे पर चलते समय सांप ने काट लिया था। उसे तुरंत ईलाज के लिए धुबड़ी मेडिकल कॉलेज लाया गया। अस्पताल के डॉ. रेजिबुल द्वारा चिकित्सा के बावजूद मोफिजुल की हालत तेजी से बिगड़ती गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने डॉ रेजिबुल पर गलत ईलाज करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि जब उन्होंने मोफिजुल को लगाए गए इंजेक्शन के बारे में जानकारी मांगी गई, तो चिकित्सक ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया।

नाव के साथ डूब रहे दो लोगों की बचाई जान

जोरहाट (हिंस)। जोरहाट में आज ब्रह्मपुत्र नद में नाव के साथ डूब रहे दो लोगों की जान बचा ली गई। असम पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज असम और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स ने एक वीरतापूर्ण बचाव अभियान चलाया। अभियान में जोरहाट के निमातीघाट में ब्रह्मपुत्र नद में नाव के साथ डूब रहे दो लोगों को बचाया गया। बाद में एसडीआरएफ ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि हम इन कठिन समय में लोगों की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

नेत्रहीन विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच नि:शुल्क *स्मार्ट विजन ग्लास* वितरित

गुवाहाटी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (आईओसीएल) ने रोटरी क्लब ऑफ गुवाहाटी मेट्रो के सहयोग से नेत्रहीन लोगों को शिक्षित व स्वावलंबी बनाने की दिसा में शानदार कार्य करते हुए 117 लोगों को स्मार्ट विजन ग्लास उपलब्ध कराया। इस कार्य को दो चरणों में विभाजित किया गया। पहले चरण में आज गुवाहाटी के छत्रीबाड़ी स्थित लोहिया लायंस ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में 90 स्मार्ट विजन ग्लास (एसवीजी) सरकारी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल व कॉटन विश्वविद्यालय के नेत्रहीन विद्यार्थियों, शिक्षकों के बीच नि:शुल्क वितरित किए गए। वितरण के बाद सभी लाभार्थियों को बैंगलोर के दो तकनीशियनों द्वारा इसका उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया गया। स्मार्ट विजन ग्लास नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए एक जीवन बदलने वाला उपकरण है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के साथ काम करता है। यह उपकरण टेक्स्ट को स्कैन करता है और ऑडियो में बदलता है। यह उन्हें असमिया और हिंदी सहित 73 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें पढ़ने (सुनने) में सक्षम बनाता है। एक नेत्रहीन व्यक्ति हस्तलिखित सामग्री भी पढ़ सकता है। वह भारतीय लहजे में अंग्रेजी पढ़ सकता है। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कार्यकारी निदेशक और राज्य प्रमुख (इंडियन ऑयल एओडी) जी. रमेश उपस्थित थे। इस परियोजना को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा उनके सीएसआर पहल के तहत पूरी तरह से वित्त पोषित किया गया है। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भास्कर ज्योति महंत, कार्यकारी निदेशक (रिटेल सेल्स)

सौरव चालिहा, डीजीएम (एचआर सीएसआर) दिगंत ठाकुरिया, जीएम (आरएस) कुंतल मुखर्जी, जीएम (वित्तीय) सुरेंद्र एच. यादव सहित आईओसीएल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद उपस्थित थे। वहीं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3240 ट्रस्ट के चेयरमैन प्रभात केडिया, सहायक गवर्नर सतीश कसेरा, क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सुरेका, सचिव एसएल अग्रवाल राजेश नांबियार, जीएम (एचआर) मंचासीन थे। अध्यक्ष श्री सुरेका ने क्लब पर विश्वास जताने और सीएसआर फंड देने के लिए आईओसीएल को तहे दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि एसवीजी के वितरण का दूसरा शिविर 30 जून को जोरहाट ब्लाइंड स्कूल में किया जाएगा, जिसके तहत 27 लाभार्थियों को यह उपकरण नि:शुल्क दिए जाएंगे। उन्होंने अपने क्लब के सहित क्लब के अन्य सदस्य सदस्यों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने 20 नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए 20 स्मार्टफोन प्रायोजित किया, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं थे। दरअसल स्मार्ट फोन के बिना एसवीजी डिवाइस काम नहीं करता है। इस मौके पर अध्यक्ष ने निजी नेत्रहीन स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों को 10 ऐसे उपकरण देने की प्रतिबद्धता जताई है, जिनका नाम सूची में नहीं है। अध्यक्ष ने आईओसीएल के जी रमेश, राजेश नांबियार, कुंतल मुखर्जी, सुरेंद्र एच यादव सहित वित्त विभाग के अधिकारियों, दिगंत ठाकुरिया और सौरव चालिहा के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इस परियोजना को लागू करने में अपनी ओर से पूर्ण मदद की। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशक भास्कर ज्योति महंत ने लाभार्थियों की सूची प्राप्त करने और इस परियोजना को सफल बनाने में रोटरी गुवाहाटी मेट्रो की मदद की थी।

असम में बनी कुकि फिल्म देशभर में हुई रिलीज

गुवाहाटी। असम में बनी, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हिंदी फिल्म कुकि 28 जून 2024 को राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई। प्रणब जे डेका द्वारा निर्देशित, यह फिल्म यह फिल्म एक बलात्कार पीड़िता की कहानी बताते हुए एक संवेदनशील मुद्दे को सामने लाती है और एक पीड़िता के मानसिक आघात के कई चरणों का वर्णन करती है। फिल्म में डेब्यू एक्टर रितिशा खोंड, बॉलीवुड के दिग्गज राजेश तैलंग, देवोलीना भट्टाचार्य, बिभूति भूषण हजारिका, रंजीव लाल बरुवा, प्रीति कंगकणा, बोधिसत्व शर्मा, दीपन्विता शर्मा, रितु शिवपुरी और कई अन्य कलाकार शामिल हैं। कान फिल्म समारोह में भाग लेकर मार्चे डू फिल्म में इस फिल्म को देखने वाले दुनिया भर के कई चलचित्र समीक्षकों द्वारा यह प्रशंसित हुआ था। फिल्म ने यूरोप और अफ्रीका के वितरकों का भी ध्यान आकर्षित किया है। फिल्म की रिलीज के बारे में खुलासा करते हुए, निर्माता डॉ. जोनमणि देवी खौंड ने फिल्म को बड़े दर्शकों तक ले जाने के महत्व पर प्रकाश डाला। हमारा उद्देश्य हमारे क्षेत्र के बाहर दर्शकों के लिए असमिया सिनेमा की गहराई और विविधता का प्रदर्शन करना है। एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में, हिंदी हमारी समृद्ध कहानियों और तकनीकी कौशल को बड़े दर्शकों के सामने पेश करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। 98 प्रतिशत असमिया कार्यबल से बनी, हिंदी भाषा की यह फिल्म असम में फिल्म उद्योग के सहयोगी प्रयासों का प्रमाण है। यह पहल उद्योग की प्रतिभा को उजागर करने के समानांतर शिक्षण और कौशल विकास के साथ-साथ सदस्यों के बीच आपसी सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है।

इंडस्ट्री के जाने-माने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के अभिनेता, गायक, संगीतकार फिल्म से जुड़े हुए हैं। यह फिल्म असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, भोपाल, जोधपुर, लखनऊ आदि शहरों में सफलतापूर्वक चल रही है।

एसएसबी क्षेत्रीय मुख्यालय, रंगिया ने मनाया अपना 11वां स्थापना दिवस

रंगिया (विभास)। भारत-भूटान सीमा के प्रहरी सशस्त्र सीमा बल, क्षेत्रक मुख्यालय रंगिया ने शुक्रवार 28 जून, 2024 को अपना 11वां स्थापना दिवस धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया। मुख्यालय के उप-महानिरीक्षक राजीव राणा के निर्देशन और मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण, गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण व प्रदर्शन और भाषण के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यालय के उप-महानिरीक्षक राजीव राणा ने सभी को मुख्यालय के 11वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं और जवानों को सुरक्षा और भाईचारे के मूल मंत्र का पालन करने और हर परिस्थिति में देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान निर्मल कुमार की कमान में पाइप बैंड और एल वीरा सिंग की कमान में फ्रंटियर

गुवाहाटी के ब्रास बैंड द्वारा सम्मान और प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम के अंतर्गत संध्या विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में 1987 बैच के अधिकारी तथा सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय गुवाहाटी के महानिरीक्षक राजिंदर कुमार भुंबला सहित दाशो ताशी वांगमो, डीसी और कर्नल कर्मा दरुकपा, एसएसपी समद्रुप जोंगखर (भूटान), बिद्युत विकास भागवती, एसीएस, डिप्टी कमिश्नर और दिगंतो कुमार चौधूरी, एपीएस, एसपी तामुलपुर, सीमांत गुवाहाटी के तहत सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी और श्रीमती नलिनी मेधी, शहीद नकुल चंद्र मेधी की मां गणमान्य व्यक्ति के रूप में उपस्थित रही।

एक्सिस बैंक ने असम में 150 से अधिक एमएसएमई को किया सम्मानित

गुवाहाटी। भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक, एक्सिस बैंक ने गतिशील और लचीले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर असम के150 से अधिक एमएसएमई ग्राहकों को सम्मानित किया। यह समारोह गुवाहाटी और अगरतला में एक्सिस बैंक की चुनिंदा शाखाओं में आयोजित किया गया। एक्सिस बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि सत्तरअली, रीजनल ब्रांच बैंकिंग हेड-ईस्ट, अंसुमन समंत राय, सर्कल हेड, नॉर्थईस्ट, ने एमएसएमई ग्राहकों को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए और उनके संबंधित क्षेत्रों और राज्य की आर्थिक वृद्धि में उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। इसके अतिरिक्त, कुछ एमएसएमई ग्राहकों को उनके व्यावसायिक परिसर में रिलेशनशिप मैनेजरों द्वारा सम्मानित किया गया। एक्सिस बैंक ने इस अवसर पर एमएसएमई के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ प्रदान करनेवाले विभिन्न किस्मके विशेष ऑफर लांच किए, जो उन्हें लागत बचाने और अधिक आसानी से तथा तेजी से ऋण

प्राप्त करने में मदद करेंगे। बैंक ने मौजूदा एमएसएमई ग्राहकों को सुरक्षित कार्यशील पूंजी उत्पादों के लिए प्रसंस्करण शुल्क पर 50 प्रतिशत छूट के साथ प्री-क्वालिफाइड ऑफर की पेश कश की। बैंक ने एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी ब्याज दर और कम प्रसंस्करण शुल्क पर अनसे क्योर्ड ईएमआई-आधारित ऋण की भी पेश कशकी। अर्निका दीक्षित, प्रेसिडेंट एंड हेड-ब्रांच बैंकिंग, एक्सिस बैंक ने इस पहल के बारे में कहा कि एक्सिस बैंक एमएसएमई को बढ़ावा देने और समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित है। बैंक यहअच्छी तरह समझता है कि भारत के आर्थिक परिदृश्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा मानना है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में एमएसएमई सेगमेंट को उन्नत डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं से लैस करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कुशल और चुस्त बने रहें। हमें अपने एमएसएमई ग्राहकों के जज्बे और उपलब्धियों का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने पर गर्व है। हमारा दृष्टिकोण *विकसित भारत* और *मेक इन इंडिया* पहल के सिद्धांतों के अनुरूप है, एवं हम एमएसएमई को समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में योगदान देने में उनकी सहायता करते हैं। देश भर में एमएसएमई लगातार नवोन्मेष और अनुकूलन के साथ सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम इन गतिशील उद्यमियों के लिए विकास को बढ़ावा देने और नए रास्ते तलाशने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले कुछ वर्षों में, एक्सिस बैंक एमएसएमई ग्राहकों को उनकी लगातार विकसित होती व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने और उनके समग्र ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई पेशकशों और पहलों के साथ सशक्त बना रहा है।

संपादकीय

गेहूं जमाखोरी पर नियंत्रण

एक खबर आई थी कि सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडारण कम हो गया है। संभव है कि गेहूं का आयात करना पड़े! दूसरी तरफ, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के डाटा पर यकीन करें, तो उसका कहना है कि किसानों ने 112.93 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया है। फसल की यह सबसे अधिक पैदावार है। बीते साल भी गेहूं 110.55 एमटी पैदा किया गया था। यानी उस उत्पादन को भी पार करके इस बार रिकॉर्ड गेहूं की फसल हुई है। यह अजीब विरोधाभास है। यदि गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है, तो सरकारी गोदामों में भंडारण कम क्यों है? क्या सरकार ने कम गेहूं खरीदा है? भारत सरकार ने गेहूं के भंडारण की अधिकतम सीमा क्यों तय की है? क्या इससे जमाखोरी पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा? अथवा कीमतों में स्थिरता आएगी? या खाद्य सुरक्षा के सकल प्रबंधन के मद्देनजर ऐसा किया गया है? भंडारण सीमा का यह निर्णय अकथनीय और दुरुह लगता है। सरकार ने फैसला किया है कि थोक के व्यापारी और खुदरा की बड़ी श्रृंखला वाले 3000 टन से अधिक का भंडारण नहीं कर सकेंगे। एकल खुदरा विक्रेता के लिए यह सीमा 10 टन तय की गई है। प्रोसेसर पिसाई की अपनी क्षमता का 70 फीसदी गेहूं या अनाज जमा रख सकते हैं। इन सभी व्यापारियों और कंपनियों को गेहूं भंडारण की अपडेट जानकारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर नियमित रूप से देनी होगी। सवाल यह है कि नियंत्रण सिर्फ गेहूं के लिए है अथवा सभी अनाजों पर यह लागू होगा? भंडारण की यह अधिकतम सीमा 24 जून, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक जारी रहेगी। गेहूं और अनाज की भंडारण सीमा, अंततः, क्यों तय करनी पड़ी? इसके बुनियादी कारण हैं कि खुदरा अनाज की मुद्रास्फीति मई में, साल-दर-साल, 8.69 फीसदी रही है। दूसरे, सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडारण एक जून को 29.91 मिलियन टन था। यह बीते 16 सालों में सबसे कम था। सर्वाधिक उत्पादन होने के बावजूद भंडारण इतना कम क्यों हुआ? तीसरे, अभी तक बहुत अच्छा मानसून नहीं हुआ है। यह चावल के उत्पादन को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि चावल के सरकारी भंडार पर्याप्त हैं। क्या खाद्य सुरक्षा पर किसी संकट के आसार हैं? गेहूं उत्पादन में तो भारत विश्व में नंबर दो का देश है। हम कई देशों को गेहूं निर्यात करते हैं। फिर गेहूं भंडारण की कमी और भंडारण सीमा का नियंत्रण समझ के परे है। गेहूं की भंडारण सीमा बीते साल जून में ही पहली बार लागू की गई थी। तब थोक विक्रेताओं और बड़े खुदरा व्यापारियों के लिए अधिकतम भंडारण की सीमा 2000 टन थी। निजी, एकल स्टोर के लिए 10 टन ही थी और प्रोसेसर के लिए पिसाई क्षमता का 75 फीसदी जमा की अनुमति थी। ये सीमा बाद में घटा कर 500 टन, 5 टन और 60 फीसदी कर दी गई। कारण आज तक अज्ञात हैं, क्योंकि बीते साल भी गेहूं का उत्पादन अच्छा हुआ था। जो सीमा घटाई गई, वह फरवरी, 2024 तक थी, लेकिन एक अप्रैल को नई फसल, नई पैदावार आने से भंडारण सीमा फिर बढ़ा दी गई। निजी व्यापारियों को बता दिया गया कि वे किसानों द्वारा लाया गया गेहूं न खरीदें। कमोबेश एक महीने तक खरीददारी न करें। यह इसलिए किया गया, ताकि सरकार अपने भंडारण को मजबूत कर सके। बहरहाल अब फसल की मार्केटिंग का मौसम गुजर चुका है और सरकार ने भंडारण की अधिकतम सीमाएं भी तय कर दी हैं, लिहाजा सवाल है कि भंडारण के नियंत्रण कैसे तय किए जाएंगे? गैर-बासमती चावल और गेहूं के निर्यात पर जो पाबंदियां हैं, रोक हैं, उन पर कैसे निगाह रखी जा सकेगी? यह भी तथ्य है कि अनाज की पैदावार रिकॉर्ड हो रही है। मोदी सरकार एक नियंत्रण को कृषि मंत्रालय के जरिए और दूसरे को उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के मंत्रालयों के माध्यम से क्रियान्वित नहीं कर सकती।

सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडारण कम हो गया है। संभव है कि गेहूं का आयात करना पड़े! दूसरी तरफ, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के डाटा पर यकीन करें, तो उसका कहना है कि किसानों ने 112.93 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया है। फसल की यह सबसे अधिक पैदावार है। बीते साल भी गेहूं 110.55 एमटी पैदा किया गया था। यानी उस उत्पादन को भी पार करके इस बार रिकॉर्ड गेहूं की फसल हुई है। यह अजीब विरोधाभास है। यदि गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है, तो सरकारी गोदामों में भंडारण कम क्यों है? क्या सरकार ने कम गेहूं खरीदा है? भारत सरकार ने गेहूं के भंडारण की अधिकतम सीमा क्यों तय की है? क्या इससे जमाखोरी पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा? अथवा कीमतों में स्थिरता आएगी? या खाद्य सुरक्षा के सकल प्रबंधन के मद्देनजर ऐसा किया गया है? भंडारण सीमा का यह निर्णय अकथनीय और दुरुह लगता है। सरकार ने फैसला किया है कि थोक के व्यापारी और खुदरा की बड़ी श्रृंखला वाले 3000 टन से अधिक का भंडारण नहीं कर सकेंगे। एकल खुदरा विक्रेता के लिए यह सीमा 10 टन तय की गई है। प्रोसेसर पिसाई की अपनी क्षमता का 70 फीसदी गेहूं या अनाज जमा रख सकते हैं। इन सभी व्यापारियों और कंपनियों को गेहूं भंडारण की अपडेट जानकारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर नियमित रूप से देनी होगी।

लोक सभा चुनावों पर भी पश्चिमी देशों ने कई प्रकार के सवाल खड़े करने के प्रयास किए थे

अब भारत को विभिन्न क्षेत्रों में अपने सूचकांक तैयार करना चाहिए

प्रह्लाद सबनानी

वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रेटिंग तय करने की दृष्टि से वित्तीय एवं विशिष्ट संस्थानों द्वारा सूचकांक तैयार किए जाते हैं। हाल ही के समय में इन विदेशी संस्थानों द्वारा जारी किए गए कई सूचकांकों में भारत की स्थिति को संभवत जान बूझकर गलत दर्शाया गया है। इन सूचकांकों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं अफ्रीका के गरीब देशों की स्थिति को भारत से बेहतर बताया गया है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में पश्चिमी देशों द्वारा जारी किए गए तीन सूचकांकों की स्थिति देखिए। सबसे पहिले उदार (लिबरल) लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग को 104 बताया गया है और भारत के ऊपर निजेर देश को बताया गया है। इसी प्रकार, आनंद (हैपीनेस) सूचकांक में भी भारत का स्थान 126वां बताया गया है जबकि पाकिस्तान को 108वां स्थान मिला है, जहां अत्यधिक मुद्रा स्फीति के चलते वहां के नागरिक अत्यधिक त्रस्त हैं। एक अन्य, प्रेस की स्वतंत्रता नामक सूचकांक में भारत को 161वां स्थान मिला है जबकि इस सूचकांक में कुल मिलाकर 180 देशों को शामिल किया गया है और अफगानिस्तान को 152वां स्थान दिया गया है, अर्थात इस सर्वे के अनुसार, अफगानिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता भारत की तुलना में अच्छी पाई गई है। पश्चिमी देशों में स्थिति इन संस्थानों द्वारा इस प्रकार के सूचकांक तैयार किए जाकर पूरे विश्व को भ्रमित किए जाने का प्रयास हो रहा है। इसी प्रकार, भारत में हाल ही में सम्पन्न हुए लोक सभा चुनावों पर भी पश्चिमी देशों ने कई प्रकार के सवाल खड़े करने के प्रयास किए थे। जैसे, इस भीषण गर्मी के मौसम में चुनाव क्यों कराए गए हैं, जिससे सामान्यजन वोट डालने के लिए घरों से बाहर ही नहीं निकले, ईवीएम मशीन में कोई खराबी तो नहीं है, आदि। परंतु, भारतीय मतदाताओं ने इन लोक सभा चुनावों में भारी संख्या में भाग लेकर पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया है। न ही, ईवीएम मशीन में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई और न ही गर्मी का प्रभाव चुनावों पर पड़ा। हालांकि सत्ताधारी दल को पिछले चुनाव की तुलना में कुछ कम स्थान जरूर प्राप्त हुए हैं परंतु देश में किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव सामान्यतः शांति के साथ सम्पन्न हो गए। साथ ही, विपक्षी दलों को पिछले चुनाव की तुलना में कुछ अधिक स्थान मिले हैं और उन्होंने भी चुनाव के परिणामों को स्वीकार कर लिया है। चुनाव की प्रक्रिया पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया है। इस सबके बावजूद पश्चिमी देशों ने पश्चिमी लोकतंत्र सूचकांक में वर्ष 2014 में भारत को 27वां स्थान दिया था और वर्ष 2023 में भारत की रैंकिंग नीचे गिराकर 41वें स्थान पर बताई गई है। जबकि वास्तव में तो इस बीच देश में लोकतंत्र अधिक मजबूत ही हुआ है, परंतु पश्चिमी देशों द्वारा भारतीय लोकतंत्र को ही जैसे खतरे में बताया जा रहा है और एक तरह से भारतीय लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। दरअसल पश्चिमी देशों में कुछ शक्तियां भारत के हितों के विरुद्ध कार्य कर रही हैं एवं ये ताकतें विभिन्न सूचकांक तैयार करने वाली संस्थाओं को प्रभावित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़तीं हैं। कुछ समय पूर्व एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया था। इस सूचकांक में यह बताया गया था कि भारत की तुलना में श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, एथीयोपिया, नेपाल, भूटान आदि देशों में भुखमरी की स्थिति बेहतर है।

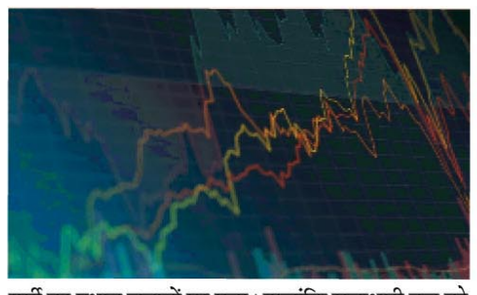

अर्थात, सर्वे में शामिल किए गए 121 देशों की सूची में श्रीलंका का स्थान 64वां, म्यांमार का 71वां, बांग्लादेश का 84वां, पाकिस्तान का 99वां, एथीयोपिया का 104वां एवं भारत का 107वां स्थान बताया गया था। जबकि पूरा विश्व जानता है कि व श्रीलंका, पाकिस्तान एवं म्यांमार जैसे देशों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी है जिसके चलते इन देशों के नागरिकों के लिए दो जून की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जबकि, भारत कई देशों को आज खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहा है। फिर किस प्रकार उक्त सूचकांक बनाकर वैश्विक स्तर पर जारी किए जा रहे हैं। ऐसा आभास हो रहा है कि भारत की आर्थिक तरक्की को विश्व के कई देश अब सहन नहीं कर पा रहे हैं एवं भारत के बारे में इस प्रकार के सूचकांक जारी कर भारत की साख को वैश्विक स्तर पर प्रभावित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। युद्ध की विभीषिका झेल रहे एथीयोपिया में नागरिक अपनी भूख मिटाने के लिए घास जैसे भारी पदार्थों को खाकर अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच जीवन यापन करने वाले नागरिकों को भुखमरी के मामले में भारत के नागरिकों से बेहतर स्थिति में बताया गया है। वहीं दूसरी ओर भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ नागरिकों को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि इन लोगों को खाने पीने सम्बंधी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। फिर भी भारत के नागरिकों को भुखमरी सूचकांक में ईथीयोपिया के नागरिकों की तुलना में इतना नीचे बताया गया है। अब कौन इस प्रकार के सूचकांकों पर विश्वास करेगा। यह भी बताया जा रहा है कि इस सूचकांक को आंकने के लिए भारत के 140 करोड़ नागरिकों में से केवल 3000 नागरिकों को ही इस सर्वे में शामिल किया गया था। इस प्रकार सर्वे का सैम्पल बनाते समय भारत जैसे विशाल देश के लिए अपर्याप्त संख्या का उपयोग किया गया है।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं अफ्रीका के गरीब देशों की स्थिति को भारत से बेहतर बताया गया है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में पश्चिमी देशों द्वारा जारी किए गए तीन सूचकांकों की स्थिति देखिए। सबसे पहिले उदार (लिबरल) लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग को 104 बताया गया है और भारत के ऊपर निजेर देश को बताया गया है।

दृष्टि कोण

नये आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में दिक्कतें

तीन नये आपराधिक कानून, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (बीएसए) 1 जुलाई, 2024 से लागू होने जा रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ ने आपराधिक प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से बनाए गए नए कानूनों की सराहना की है और उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जबकि कानूनी बिरादरी के एक वर्ग ने इन कानूनों के कुछ प्रावधानों की अनिश्चितता, अस्पष्टता और संवैधानिकता के बारे में गम्भीर चिंता जताई है। ममता बनर्जी सहित विपक्षी राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि नये अधिनियमों को तब तक स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक कि लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य उनकी संस्तुति नहीं कर देते। उनका तर्क है कि ये कानून संसद में बिना किसी सार्थक बहस के जल्दबाजी में पारित कर दिए गए थे, क्योंकि अधिकांश विपक्षी सदस्य निलम्बित थे। नए आपराधिक कानूनों की वैधता के बारे में इतनी देरी से चिन्ता व्यक्त करना अवसरों को गंवाने के अलावा और कुछ नहीं है, ये कानून तीन साल की लम्बी परामर्श प्रक्रिया और हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद बनाए गए थे। इसके बाद गृह मंत्रालय की संसदीय समिति द्वारा इन कानूनों की गहन जांच की गई थी। यहां तक कि दो अलग-अलग अवसरों पर सार्वजनिक नोटिस के जरिए जनता से सुझाव भी मांगे गए थे। सरकार इनमें से किसी भी मांग के आगे नहीं झुक रही है और कानूनों को लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रही है। इसके अतिरिक्त, नए प्रावधानों की असंवैधानिकता के बारे में चिंताएं इस तथ्य के मद्देनजर सही नहीं हैं कि बीएनएस में बदलाव मुख्य रूप से नवतेज जौहर (2018), जोसेफ शाइन (2018) और पी. रथिनम (1994) के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का प्रतिबिम्ब है। भारतीय न्याय संहिता से राजद्रोह की धारा हटाना राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में शीर्ष अदालत में केन्द्र सरकार के हलफनामे पर क्रियान्वयन दर्शाता है, साथ ही इसमें लम्बे समय से लम्बित राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को भी सम्बोधित किया गया है। बीएनएसएस और बीएसए में संशोधनों पर आपत्तियां भी उचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि इनके मूल रूप से आपराधिक कार्रवाई का डिजिटलीकरण और पीड़ित तथा नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रावधानों को शामिल करना है। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण जांच और त्वरित न्याय की मांग को पूरा करने के लिए आपराधिक प्रक्रियाओं को फिर से स्थापित किया गया है। विशेषज्ञों की अलग-अलग राय के बावजूद, नये कानूनों का क्रियान्वयन आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के बुनियादी ढांचे का निर्माण, हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, नियम और संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित करना, मानक प्रपत्रों में संशोधन करना और परिचालन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए अन्तर-एजेंसी समन्वय करना शामिल है। साथ ही एक बात जो विश्वास दिलाती है कि ये कानून समय पर लागू होंगे यह है कि एक अनुभवी और समय-परीक्षणित आपराधिक न्याय प्रणाली अस्तित्व में है जिसमें किसी भी बदलाव को अपनाने और सीमित संसाधनों के साथ किसी भी समस्या का व्यावहारिक समाधान खोजने की कुव्वत है। नये कानून तय समय पर लागू होंगे, इसका एक और आश्वासन इस हकीकत से भी मिलता है कि पुलिस, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को बड़े पैमाने पर क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण दिया गया है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है। हालांकि, कानून लागू करने की व्यवस्था से जुड़े कुछ अधिकारी अभी भी आशंकित हैं, उनका तर्क है कि नए कानूनों के सफल प्रवर्तन से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अभी भी सम्बोधित किया जाना बाकी है, ताकि अधिनियमों का निर्बाध प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। बीएनएसएस में कई अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं, जिसमें तलाशियों, जब्तियों और अपराध के दृश्य की वीडियोग्राफी और केस प्रॉपर्टी आदि की फोटोग्राफी शामिल है, जिनके लिए शुरुआत से ही इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल तकनीकी का प्रयोग करना आवश्यक होगा। हालात यह है कि सभी जांचकर्ताओं और निर्णायकों को अभी भी उपयुक्त उपकरण और तकनीकी प्रदान करके उनका उपयोग करना सिखाना अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है, ताकि आवश्यक डिजिटल आउटपुट समान रूप से और स्वीकार्य रूप में उत्पन्न, सुरक्षित और संगृहीत किए जा सकें। इसके अतिरिक्त, ई-कोर्ट कार्यवाही का संचालन और इलेक्ट्रॉनिक संचार आदि के माध्यम से समन और वारंट भेजने सहित कई अन्य प्रक्रियाएं हैं, जिनके लिए अदालतों, पुलिस स्टेशनों और जेलों का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण, नियमों का मानकीकरण, तकनीकी और सहायक कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण, वित्तीय संसाधन और अंतर-एजेंसी समन्वय अति आवश्यक होंगे। जमीनी हकीकत यह है कि अभी तक अधिकांश राज्यों में इस दिशा में कुछ भी ठोस नहीं किया गया है।

कुछ अलग

भ्रष्टाचार के पुल

बरसात आने से पहले ही बिहार में एक सप्ताह के भीतर एक के बाद एक तीन पुलों का गिरना सार्वजनिक निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार व धांधलियों को बेनकाब करता है। लगातार धड़ाधड़ गिरते पुल न केवल ठेकेदारों बल्कि उन्हें संरक्षण देने वाले राजनेताओं पर भी सवालिया निशान लगाते हैं। एक सप्ताह के भीतर बिहार के मोतिहारी में रविवार को एक पुल गिरने की तीसरी घटना हुई। इससे पहले अररिया और सिवान में भ्रष्टाचार के पुल गिरे थे। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में डेढ़ करोड़ की लागत से बनने वाला जो पुल गिरा, उसकी एक दिन पहले ही ढलाई हुई थी। रात में पुल भरभरा कर गिर गया। यदि यह पुल यातायात खुलने के बाद गिरता तो न जाने कितनी जानें चली जातीं। आरोप है कि घटिया सामग्री के कारण पुल बनने से पहले गिर गया। शनिवार को सिवान में गंडक नहर पर बना तीस फीट लंबा पुल गिर गया, जो चार दशक पहले बना था। इसी तरह मंगलवार को अररिया में बारह करोड़ की लागत से बना पुल गिर गया था। पुल के तीन पाये ध्वस्त हो गए थे। बिहार में निर्माण कार्यों में धांधलियों का आलम यह है कि पिछले पांच सालों के दौरान दस पुल निर्माण के दौरान या निर्माण कार्य पूरा होते ही ध्वस्त हो गए। उल्लेखनीय है कि बीते साल जून में भागलपुर में गंगा नदी पर करीब पौने दो हजार करोड़ की लागत से बन रहे पुल के गिरने पर भारी शोर मचा था। लेकिन उसके बाद भी हालात नहीं बदले। पुलों के गिरने का सिलसिला यूं ही जारी है। जो बताता है कि नियम-कानून ताक पर रखकर बेखौफ घटिया सामग्री वाले सार्वजनिक निर्माण कार्य जारी हैं। जाहिर है ऊपर से नीचे तक की कमीशनखोरी और जनता की कीमत पर मोटा मुनाफा कमाने वाले ठेकेदारों की मनमानी जारी है। तभी निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग बेखौफ किया जा रहा है। यदि शासन-प्रशासन का भय होता तो पुल यूं धड़ाधड़ न गिर रहे होते। सवाल ये उठता है कि आजादी के सात दशक बाद भी हम देश की विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता की निगरानी करने वाला तंत्र क्यों विकसित नहीं कर पाए? यह जरूरी है कि सार्वजनिक निर्माण गुणवत्ता का हो और उसका निर्माण कार्य समय पर पूरा हो। इन योजनाओं को इस तरह डिजाइन किया जाए, जिससे कई पीढ़ियों को उसका लाभ मिल सके। साथ ही वह दुर्घटनामुक्त और जनता की सुविधा बढ़ाने वाला हो। मगर विडंबना देखिए कि बिहार के पुल उद्घाटन से पहले ही धराशायी हो रहे हैं। स्पष्ट है कि मोटे मुनाफे के लिए घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरा निष्कर्ष यह है कि जिन लोगों का काम निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी करना होता है, वे आंखें मूंदे बैठे हैं। जो समाज में मूल्यों के पराभव व आपराधिक तत्वों की निर्माण कार्यों में गहरी दखल को ही दर्शाता है। यही वजह है कि भारी यातायात के दबाव वाले दौर में पुल अपना ही बोझ नहीं संभाल पा रहे हैं। यूं तो कभी किसी हादसे की वजह से भी पुल गिर सकते हैं, मगर निरंतर कई पुलों का कुछ ही दिनों में गिरना साफ बताता है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। जिसमें भ्रष्टाचार की बड़ी भूमिका है। दरअसल, सार्वजनिक निर्माण की गुणवत्ता की यदि समय-समय पर जांच होती रहे तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता था। इन हादसों की वजह यह भी है कि राजनेताओं व दबंगों के गठजोड़ से ऐसे लोगों को ठेके मिल जाते हैं, जिनको न तो बड़े निर्माण कार्यों का अनुभव होता है और न ही गुणवत्ता को लेकर किसी तरह की प्रतिबद्धता होती है।

देश दुनीया से

अविरल यमुना दूर करेगी दिल्ली की प्यास

दिल्ली में यमुना नदी को नया जीवन देने के लिए नौ साल पहले राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अर्थात् एनजीटी ने एक आदेश दिया था कि नदी का जहां तक बहाव है, उसका सीमांकन किया जाए। हालांकि, यमुना द्वारा गर्मी में छोड़ी गई जमीन पर कब्जा करने में न सरकारी महकमे पीछे रहे और न ही भूमाफिया। इसके बाबत एक कमेटी भी बनी थी जिसे मौके पर जाकर उस स्थान तक चिन्हित करना था, जहां अपने सम्पूर्ण यौवन पर आने के दौरान नदी का अधिकतम विस्तार होता है। कभी किसी ने नहीं जाना कि सावन-भादों में जब नदी उफान पर होती है तो उसे तसल्ली से बहने के लिए कितनी भूमि चाहिए। न ही कभी परवाह की गई कि नदी की गहराई कम होने से किस तरह समूचा जल-तंत्र गड़बड़ा रहा है। यह बात सरकारी दस्तावेजों में जरूर दर्ज है कि यमुना नदी के दिल्ली प्रवेश वजीराबाद बैराज से लेकर ओखला बैराज तक के 22 किलोमीटर में 9700 हेक्टेयर की कछार भूमि पर अब पक्के निर्माण हो चुके हैं। इसमें से 3638 हेक्टेयर को दिल्ली विकास प्राधिकरण खुद नियमित बना चुका है। इसके अलावा वैध-अवैध अतिक्रमण हर साल बढ़ रहे हैं। समझना होगा कि अरावली से चलकर नजफ़गढ़ झील में मिलने वाली सहाबी नदी और इस झील को यमुना से जोड़ने वाली नैसर्गिक नहर का नाला बनना हो या फिर सारे कालेखान के पास बारा पुला या फिर साकेत में खिड़की गांव का सात पुला या फिर लोधी गार्डन की नहरें, असल में ये सभी यमुना में जब कभी क्षमता से अधिक पानी आ जाता तो उसे जोहड़-तालाब में सहेजने का जरिया थीं। शहर को चमकाने के नाम पर इन सभी सदियों पुरानी संरचनाओं को तबाह कर दिया गया। अब न बरसात का पानी तालाब में जाता है और न ही बरसात के दिनों में सड़कों पर जल जमाव रुक पाता है। एनजीटी हर साल आदेश देता है लेकिन सरकारी महकमे भी कागज की नाव चलाकर उन आदेशों को पानी में डुबो देते हैं। दिल्ली में अधिकांश जगह पक्की सड़क या गलियां हैं, यहां से बरसात के पानी को झील-तालाबों तक कम से कम हानि के ले जाना सरल है। दुर्भाग्य है कि इस शहर में बरसने वाले पानी का अस्सी फीसदी गंदे नालों के जरिए नदी तक पहुंचने में ही बर्बाद हो जाता है। नदी भी अपनी क्षमता से पचास फीसदी कम चौड़ी और गहरी रह गई है। इसमें बरसात के पानी से अधिक तो गंदा मल-जल और औद्योगिक कचरा आता है। यमुना की गहराई घटने का क्या दुष्परिणाम होता है उसके लिए वजीराबाद जल संयंत्र का उदाहरण काफी है। यह संयंत्र वजीराबाद बैराज के पास बने जलाशय से पानी लेता है। जलाशय की गहराई 4.26 मीटर हुआ करती थी। लेकिन इसकी गाद को किसी ने साफ करने की सोची नहीं और अब इसमें महज एक मीटर से भी कम 0.42 मीटर जल-भराव क्षमता रह गई। तभी 134 एमजीडी क्षमता वाला संयंत्र आधा पानी भी नहीं निकाल पा रहा। आज दिल्ली पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है लेकिन यह कोई तकनीकी और दूरगामी हल नहीं है। दिल्ली शहर के पास यमुना जैसे सदानीर नदी का 42 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। इसके अलावा छह सौ से ज्यादा तालाब हैं जो कि बरसात की कम से कम मात्रा होने पर भी सारे साल महानगर का गला तर रखने में सक्षम हैं। यदि दिल्ली की सीमा में यमुना की सफाई के साथ-साथ गाद निकाल कर पूरी गहराई मिल जाए। इसके साथ ही सभी नाले गंदा पानी छोड़ना बंद कर दें तो महज 30 किलोमीटर नदी, जिसकी गहराई दो मीटर हो तो इसमें निर्मल जल साल भर रह सकता है। दिल्ली के हर घर को पर्याप्त जल मिल सकता है। विदित हो नदी का प्रवाह गर्मी में कम रहता है लेकिन यदि गहराई होगी तो पानी का स्थाई डेरा रहेगा। हरियाणा सरकार इस्राइल के साथ मिलकर यमुना के कायाकल्प की योजना बना रही है। इस दिशा में सिंचाई विभाग ने अपने सर्वे में पाया है कि यमुना में गंदगी के चलते दिल्ली में सात माह पानी की किल्लत रहती है। दिल्ली में यमुना, गंगा और भूजल से 1900 क्यूसेक पानी प्रतिदिन प्रयोग में लाया जाता है। सन् 2019 में यमुना नदी के किनारों पर एक प्रयोग किया गया था। वहां गहरे गड्ढे बनाए गए थे ताकि जब पानी एकत्र हो तो इनके जरिए जमीन में समा जाये। इसके अच्छे परिणाम भी आए लेकिन फिर उस परियोजना में जमीन से अधिक कागज पर खतियां खोदी जाने लगीं। वैसे एनजीटी वर्ष 2015 में ही दिल्ली के यमुना तटों पर हर तरह के निर्माण पर पाबंदी लगा चुका है।

नौ साल पहले राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अर्थात् एनजीटी ने एक आदेश दिया था कि नदी का जहां तक बहाव है, उसका सीमांकन किया जाए। हालांकि, यमुना द्वारा गर्मी में छोड़ी गई जमीन पर कब्जा करने में न सरकारी महकमे पीछे रहे और न ही भूमाफिया। इसके बाबत एक कमेटी भी बनी थी जिसे मौके पर जाकर उस स्थान तक चिन्हित करना था, जहां अपने सम्पूर्ण यौवन पर आने के दौरान नदी का अधिकतम विस्तार होता है। कभी किसी ने नहीं जाना कि सावन-भादों में जब नदी उफान पर होती है तो उसे तसल्ली से बहने के लिए कितनी भूमि चाहिए।

आप का नजरीया

अब पक्ष-विपक्ष मिलकर चलाएं सरकार

देश में लंबे चले चुनाव अभियान और चुनाव परिणाम के बाद अस्तित्व में आयी 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राजग की लगातार तीसरी पारी गठबंधन सरकार के रूप में सामने आई है। निश्चित रूप से इस बार विपक्षी गठबंधन पिछले दशक के मुकाबले ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी का विपक्ष का नेता चुना जाना साफ बताता है कि आने वाले दिनों में राजग सरकार की राह आसान नहीं रहने वाली। इस संक्षिप्त सत्र के दूसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सत्ता-पक्ष व विपक्ष के बीच जो तनातनी सामने आई, वह पिछले सात दशकों के मुकाबले अभूतपूर्व है। विपक्ष एक ओर लोकसभा उपाध्यक्ष पद देने की मांग कर रहा था, तो सत्ता पक्ष ऐसा करने को तैयार नहीं था। जाहिर इस टकराव के बीच लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने की स्थितियां बनी हैं। हालांकि, राजग सरकार के पास चुनाव पूर्व गठबंधन के चलते पूर्ण बहुमत है, लेकिन विपक्ष इस चुनाव को अपनी एकजुटता के रूप में एक प्रतीकात्मक दबाव के रूप में दिखाना चाहेगा। बहरहाल, बेहतर होता कि लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों पर चयन सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच सहमति से होता। इसी तरह नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिये नियुक्त प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर भी सत्ता पक्ष व विपक्ष में तनातनी देखी गई। वरिष्ठता के क्रम में इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस की दावेदारी की गई थी। बहरहाल, 18वीं लोकसभा की शुरुआत में ही पक्ष-विपक्ष के बीच तनातनी की शुरुआत स्वस्थ लोकतंत्र के लिये अच्छा संकेत तो कदापि नहीं है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि 17वीं लोकसभा के दौरान टकराव के चलते तमाम सत्रों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहा। उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 2023 में शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में घुसपैठ के मामले में बहस की मांग पर कथित दुर्व्यवहार हेतु 141 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। जिसमें 95 लोकसभा सदस्य थे। उम्मीद की जानी चाहिए 18वीं लोकसभा में वैसे दृश्य फिर न देखने को मिलें। जनता अपने प्रतिनिधियों को इस लिये चुनकर संसद में भेजती है ताकि वे उनके इलाके के विकास को नई दिशा दे सकें। लेकिन पहले दिन विपक्षी नेताओं द्वारा संसद में संविधान की प्रतियों के साथ एकजुटता दर्शाना और कतिपय सत्तारूढ़ दल के सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान नारेबाजी को देखकर लगता है कि विपक्ष ज्यादा मुखर होकर सरकार के लिये चुनौती पेश करता रहेगा। बहरहाल, किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात में है कि सरकार सहमति से चले। साथ ही विपक्ष भी जिम्मेदार भूमिका में नजर आए। कुल मिलाकर हंगामे, बहिष्कार व नारेबाजी के बजाय रचनात्मक व गरिमामय भूमिका की दरकार है। स्वस्थ लोकतंत्र की दरकार है सरकार के निर्णयों में हर छोटे-बड़े राजनीतिक दल की भागीदारी हो।

उदयपुर में दो युवकों की डूबने से मौत

उदयपुर (हिंस)। उदयपुर शहर में शुक्रवार को दो युवक अलग-अलग स्थानों पर डूब गए। एक युवक फतहसागर झील में तो दूसरा गंगू कुंड में डूबा। पुलिस के अनुसार फतहसागर में ओवरफ्लो के पास अन्य लोगों के साथ नहा रहे युवक टेकरी-मादड़ी लिंक रोड निवासी मंथन अधिकारी (34) पुत्र देवेन्द्र अधिकारी की डूबने से मौत हो गई। उसने जैसे ही ट्यूब छोड़ा वह खुद को संभाल नहीं सका और गहराई में चला गया। इसी तरह, गंगू कुंड पर किनारे पर बैठकर नहा रहा आय? निवासी प्रहलाद (39) पुत्र नाथूलाल खटीक गहराई की तरफ फिसल गया। उसे तैरना नहीं आता था। उसे बचाया नहीं जा सका।

पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने शुरू की तैयारियां

जयपुर (हिंस)। राजस्थान में विधायकों के लोकसभा सदस्य चुने जाने के कारण पांच विधानसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें दौसा, देवली-उनियारा, झुंझुनूं, खींवसर और चौरासी है। झुंझुनूं, देवली-उनियारा और दौसा में कांग्रेस का कब्जा था जबकि खींवसर में कांग्रेस गठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और चौरासी में भारत आदिवासी पार्टी काबिज थी। अब तक उपचुनाव में कांग्रेस सत्ता में रहे या विपक्ष में उसका पलड़ा हमेशा भारी रहा है। पिछले 10 सालों में विधानसभा की 20 और लोकसभा की दो सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। दो लोकसभा सहित 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा ने चार, रालोपा ने एक और

बीएपी ने एक सीट जीती है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय वर्ष 2019 से लेकर 2022 तक 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे जिनमें से 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने मंडावा, सुजानगढ़, सरदारशहर, सहाड़ा, धरियावद, वल्लभनगर और रामगढ़ सीट जीती थी। भाजपा ने राजसमंद और आरएलपी ने खींवसर सीट पर उपचुनाव जीता था। 2014 से लेकर 2018 तक मोदी लहर के बावजूद भी नसीराबाद, वैर, सूरतगढ़ और मांडलगढ़ सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की जबकि भाजपा के खाते में धौलपुर और कोटा दक्षिण सीट की आ पाई थी। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने विधानसभा की 163 सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया, लेकिन कांग्रेस ने 2018 में अजमेर और अलवर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। भाजपा के सत्ता में आने के बाद साल 2024 में श्रीकरणपुर सीट पर हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत के चलते उस सीट पर उपचुनाव हुए थे। वहीं, हाल ही में बागीदौरा उपचुनाव में कांग्रेस गठबंधन की सहयोगी भारत आदिवासी पार्टी ने जीत दर्ज की है।

सेंगोल मुद्दे पर मायावती बोलीं सपा के सभी हथकंडों से रहें सावधान

लखनऊ (हिंस)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सेंगोल मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) पर हमला बोला है। उन्होंने सपा पार्टी के सभी हथकंडों से जरूर सावधान रहने की सलाह दी हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया की साइड *एक्स* पर पोस्ट करते हुए कहा कि सेंगोल को संसद में लगाना या नहीं, इस पर बोलने के साथ-साथ सपा के लिए यह बेहतर होता कि यह पार्टी देश के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में तथा आम जनहित के मुद्दों को भी लेकर केन्द्र सरकार को घेरती। उन्होंने कहा कि जबकि सच्चाई यह है कि यह पार्टी अधिकांश ऐसे मुद्दों पर चुप ही रहती है और सरकार में आकर कमजोर वर्गों के विरुद्ध फैसले भी लेती है। इनके महापुरुषों की भी उपेक्षा करती है। इस पार्टी के सभी हथकंडों से जरूर सावधान रहें। उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी ने संसद भवन में सेंगोल को हटाकर उसके स्थान पर संविधान रखने की मांग की है। सपा ने सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताया है। वहीं, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हुए कहा है कि सेंगोल पर सपा की मांग गलत नहीं है।

पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने किया आक्रोश मार्च

जींद (हिंस)। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने जींद में प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय ओपीएस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके बाद समिति के पदाधिकारियों ने सफीदों रोड पर स्थित बैरागी धर्मशाला से शहीदी स्मारक तक आक्रोश मार्च किया। इस दौरान कर्मचारियों की भारी भीड़ उमड़ी और रोड पर लंबी लाइन लग गई। इस मौके पर विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी पिछले कई वर्षों से ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर पेंशन बहाली संघर्ष समिति प्रदेश में कई बड़े आंदोलन कर चुकी है, जिसके दबाव में हरियाणा सरकार ने 20 फरवरी 2024 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन भी किया गया। उसके बावजूद भी अभी तक सरकार ओपीएस बहाली के लिए कोई फैसला नहीं ले सकी, जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। मंच का संचालन कर रहे राज्य महासचिव ऋषि नैन ने कहा कि संघर्ष समिति पिछले 7 सालों से ओपीएस बहाली की मांग कर रही है, उसके बावजूद भी सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए संघर्ष समिति अब सभी जिलों में काले कपड़ों में पेंशन आक्रोश मार्च करेगी। जींद जिला प्रधान जोगिंद्र लोहान और राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप लाठर ने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले भी संघर्ष समिति जींद में बड़ी रैली कर सरकार को चेता चुकी है कि जल्द से जल्द ओपीएस बहाल करे नहीं तो संघर्ष समिति वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई जाएगी। अनूप लाठर ने कहा कि 25 जून को संघर्ष समिति ने सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्री को ओपीएस बहाली के लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने कोई फैसला न लिए जाने के चलते संघर्ष समिति ने आंदोलन तेज कर दिया है। जिसकी शुरुआत जींद से की गई। अब सभी जिलों में आक्रोश मार्च किया जाएगा। 1 सितंबर को पंचकूला में रैली कर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। राजबाला कौशिक ने कहा कि पेंशन आक्रोश मार्च में जींद जिले के सभी कर्मचारी संगठन शामिल हुए।

बीएसएफ डीजी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात जवानों की परिचालन तत्परता को देखा

जम्मू (हिंस)। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने शुक्रवार को जम्मू के सीमांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात जवानों की परिचालन तत्परता की समीक्षा की। आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार डीजी अग्रवाल ने सांबा सीमा क्षेत्र में तैनात बीएसएफ जवानों की परिचालन तत्परता की समीक्षा की। उन्होंने सेक्टर कमांडर और बटालियन कमांडेंट से विस्तृत जानकारी ली। दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को यहां पहुंचे डीजी बीएसएफ ने जवानों से बातचीत की और उनके समर्पण और व्यावसायिकता की सराहना की।

कांग्रेस सरकार बनने पर हरियाणा में बदमाशों को रहने नहीं देंगे : भूपेंद्र सिंह हुड्डा

फरीदाबाद (हिंस)। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार बनने पर हरियाणा में बदमाशों को रहने नहीं देंगे। सुरक्षित फरीदाबाद, सुरक्षित हरियाणा, विकसित हरियाणा बनाना कांग्रेस का मकसद है। वे शुक्रवार को फरीदाबाद में धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान, विधानसभा में कांग्रेस के उप-नेता आफताब अहमद और विधायक नीरज शर्मा, शारदा राठौर पूर्व विधायक, रघुवीर तेवतिया पूर्व विधायक, ललित नागर पूर्व विधायक, लखन सिंगला, विजय प्रताप समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लडने और बीजेपी को कड़ा मुकाबला देने के लिए कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि आधा मोर्चा आप लोगों ने फतेह कर लिया है। 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव में पूरा मोर्चा फतह करने का मौका है।

इस बार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की सारी विधानसभाओं में कांग्रेस /संजीवकी जीत ही हमारा लक्ष्य है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि फरीदाबाद हरियाणा का सबसे पुराना औद्योगिक नगर है। लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई है, उसने इलाके की जनता को आधारभूत सुविधाओं के लिए भी तरसा रखा है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में यहां आईएमटी, सिक्स लेन सड़कें, गुड़गांव वाली रोड, बाईपास, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, बड़े उद्योग, संस्थाएं, वाटर सप्लाई और सीवरेज व्यवस्था स्थापित की थी। लेकिन बीजेपी ने सिर्फ जनता को पानी की किल्लत, गंदे पानी की सप्लाई, सड़कों और सीवरेज के जाम जैसी समस्याओं में उलझाकर रख दिया। 10 साल में यहां कोई भी बड़ी परियोजना, कोई बड़ी संस्था या बड़ा उद्योग नहीं आया। लगातार उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से अकेले फरीदाबाद में एक लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। इससे पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता चंद्रपाल, कमल सिंह तेवतिया, डा. हेतराम चौहान, अमित कुमार, जगदीश बैनीवाल, मदन प्रधान, वदेत सिंह, रमेश, रविन्द्र के अलावा इनेलो जिला सैनक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रणवीर सिंह ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर उनका पार्टी में आने पर स्वागत किया। कार्यक्रम का मंच संचालन विधायक एवं फरीदाबाद प्रभारी आफताब अहमद द्वारा किया गया। इस अवसर पर मनधीर मान, गुलशन बगगा, ठाकुर राजाराम, गिरीश भारद्वाज, नीटू मान, योगेश, अब्दुल गफ्फार कुरैशी, गजना लाम्बा, मुनेश शर्मा, भारत अरोड़ा सहित अनेकों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।

प्रॉपर्टी कारोबारी की सिर में गोली लगने से मौत गोली चली या गोली मारी जांच में जुटी पुलिस

जयपुर (हिंस)। जयपुर ग्रामीण जिले के जमवारामगढ़ थाना इलाके में गुरुवार रात कार में शराब पार्टी करने के दौरान गोली लगने से एक प्रोपट्री कारोबारी की मौत हो गई। घटना के बाद कार में सवार एक युवक फरार हो गया, जबकि दो साथियों को पकड़ कर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार चार दोस्त गुरुवार रात कार में शराब पार्टी करते हुए अपने दोस्त के घर खाना खाने जा रहे थे। जयपुर स्टेट हाइवे पर अस्थल गांव में अचानक प्रोपट्री कारोबारी के सिर में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसके दोस्त उसे लेकर सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे, जहां पर उसकी मौत हो गई। गोली लगने से जमवारामगढ़ (जयपुर) की खसानों की ढाणी लाली निवासी मुकेश गुर्जर (26) पुत्र भौरी लाल की मौत हो गई। गोली उसके सिर के पीछे वाले हिस्से में लगी है। थानाधिकारी हरदयाल मीणा ने बताया कि गोली लगने की घटना के बाद दोस्त उसे अस्पताल में भर्ती करवाया कर फरार हो गए थे।

सीएम रोजगार उत्सव : जयपुर और ग्रामीण जिले के डेढ़ हजार से अधिक नवनियुक्त अभ्यर्थी लेंगे भाग

जयपुर (हिंस)। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत शनिवार को जयपुर के मानसरोवर स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नवनियुक्त कार्मिकों से संवाद करेंगे। जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के सफल आयोजन के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) सुरेश कुमार नवल को प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) अल्का विश्नोई को सह प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही जिला कलक्टर ने आवश्यक व्यवस्थाएं एवं इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में जयपुर ग्रामीण के कुल 1 हजार 500 से ज्यादा नवनियुक्त कार्मिक शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि जयपुर जिले में नियुक्ति पाने वाले 1 हजार 276 एवं जयपुर ग्रामीण जिले में नियुक्ति प्राप्त करने वाले 230 सहित दोनों जिलों के कुल 1 हजार 506 नवनियुक्त कार्मिक राज्य स्तरीय समारोह के साक्षी बनेंगे।

नीट पेपर लीक मामले में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के दस छात्रों से पूछताछ

झाला वाड़ (हिंस)। मेडिकल की राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) में डमी कैंडिडेट बैठाए जाने के मामले में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के भी दस स्टूडेंट्स का नाम सामने आया है। इस मामले में दिल्ली और मुंबई की पुलिस झालावाड़ आई और नीट यूजी परीक्षा के संबंध में झालावाड़ में दो स्टूडेंट्स से पूछताछ की और अपने साथ ले गई। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज डीन सुभाष जैन के मुताबिक अब तक जानकारी सामने आई है कि दस मेडिकोज स्टूडेंट के नाम डमी कैंडिडेट में शामिल है, इनमें से आठ मेडिकल स्टूडेंट को पूछताछ के बाद छोड़ दिया, जबकि पंद्रह दिन पहले लेकर गए दो मेडिकल स्टूडेंट से अभी भी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों के साथ छात्राएं भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नीट परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनने के संबंध में

झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे कुछ एमबीबीएस के स्टूडेंट के नाम भी दिल्ली और मुंबई पुलिस के सामने आए थे। इस मामले में लाखों रुपये लेकर डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी गई। आठ मई को दिल्ली पुलिस के अधिकारी झालावाड़ आए। उन्होंने आठ स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी मांगी। इसके बाद तेरह जून को मुंबई पुलिस के अधिकारी झालावाड़ आए और एक छात्रा समेत दो स्टूडेंट्स की जानकारी मांगी। तेरह जून को झालावाड़ में ही शाम 6 बजे तक मुंबई पुलिस ने छात्र व छात्रा से पूछताछ की। इसके बाद दोनों को अपने साथ मुंबई ले गए। इसकी जानकारी लोकल पुलिस को कॉलेज की ओर से दी गई थी। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों स्टूडेंट्स 2022 बैच के हैं। दोनों राजस्थान के हैं। बाकी आठ स्टूडेंट्स राजस्थान व अन्य राज्यों से हैं। ये 8 स्टूडेंट्स 2019, 2021 और 2022 बैच के हैं। मेडिकल कॉलेज की जांच कमेटी अपने स्तर पर भी जांच कर रही है। नीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा होने के अब तक कई मामले सामने आए है और मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। इन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

बिगड़ती कानून-व्यवस्था सरकार की लचर कार्यप्रणाली का नतीजा : दलबीर किरमारा

हिसार (हिंस)। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष दलबीर किरमारा ने दिन-प्रतिदिन बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए इसके लिए भाजपा सरकार की लचर कार्यप्रणाली को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधियों पर ईडी, सीबीआई व अन्य एजेंसियों की कार्रवाई करने वाली भाजपा सरकार नागरिकों की जानमाल की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। हिसार शहर में तीन दिनों में तीन व्यापारियों से रंगदारी मांगे जाने की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जिला अध्यक्ष दलबीर किरमारा ने शुक्रवार को कहा कि यह सब सरकार की लचर कार्यप्रणाली का नतीजा है। विधानसभा के चुनाव अभी दूर है लेकिन सरकार ने विधानसभा चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है।

गो आधारित वैश्विक निवेश राजस्थान इकाई का सम्मेलन एक जुलाई को

बीकानेर (हिंस)। गो आधारित वैश्विक निवेश की राजस्थान इकाई का सम्मेलन 1 जुलाई को राजमहल होटल में 3 बजे होगा। राजस्थान गो सेवा परिषद और जीसीसीआई राजस्थान के पदाधिकारी और सदस्यों समेत गो सेवा से जुड़े लोगों को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. वल्लभ भाई कथिरिया के साथ गोचर आंदोलन के मुद्दे पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, अधिष्ठाता स्वामी विमर्शानंद, राजस्थान गो सेवा परिषद अध्यक्ष हेम शर्मा, प्रो. वाइस चांसलर डा. हेमंत दाधीच शामिल होंगे। राजस्थान जीसीसीआई सम्मेलन में सदस्य व पदाधिकारी

की भूमिका में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इस सम्मेलन में गो आधारित उद्यमिता के विकास में राजस्थान प्रदेश स्तर पर गो उत्पादों की मार्केटिंग, मेंन्यूफक्चरिंग, उत्पादों की क्वालिटी, विभिन्न स्तरों पर कोर्डिनेशन, नेचुरल फार्मिंग, बायो गैस, हेल्थ न्यूट्रीशन, पंचगव्य थेरेपी, गो प्रोडेक्शन, डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, गोचर संरक्षण और विकास, वेलिडेशन स्टेबिलिटी, डेयरी प्रोडक्ट, नस्ल संवर्धन, सीएसआर फंड आदि में स्टेट इकाई की सक्रियता सुनिश्चित कर प्रदेश स्तर पर गो उद्यमिता को संबल दिया जाना है।

जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली रवाना

पटना (हिंस)। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को दिल्ली रवाना हो गये। दिल्ली में 29 जून को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते नीतीश बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसमें पार्टी को अन्य राज्यों में विस्तार, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति और कई अहम पदों पर नेताओं को खास जिम्मेदारी देने जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा बैठक में कई एजेंडों को लेकर प्रस्ताव पास किये जा सकते हैं। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार में पार्टी के मंत्रीगण, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामत, राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेता संजय झा सहित सभी वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहेंगे।

जिप सदस्य हत्याकांड मे तीन अज्ञात पर प्राथमिकी, पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी

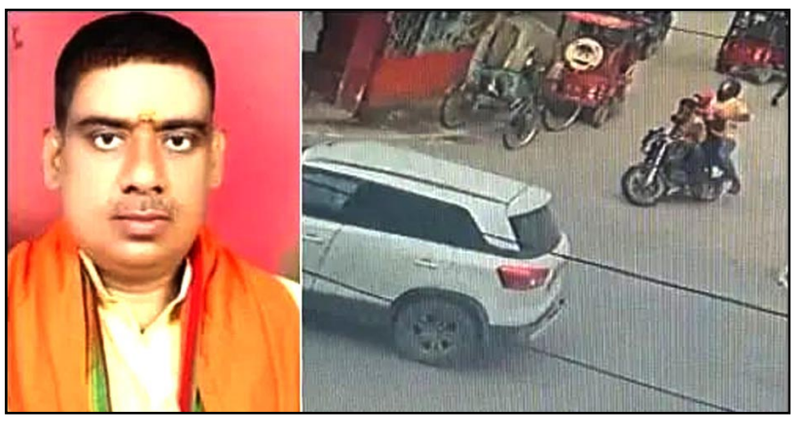

पूर्वी चंपारण (हिंस)। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 के जिप सदस्य सुरेश यादव की गोली मार हत्या मामले में गुरुवार को सुरेश के भाई विजय यादव ने नगर थाना में तीन अज्ञात लोगो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। वही घटना को लेकर एसपी कांतेश कुमार मिश्र द्वारा गठित एसआइटी अपराधियो के विरुद्ध ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए सात से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बुधवार से गुरुवार देर रात तक जिले के सुगौली, रघुनाथपुर, हरसिद्धि, अरेराज, पिपराकोठी व बंजरिया थाना क्षेत्र के कई इलाके में छापेमारी की गई। पुलिस का कहना है कि हत्या में शामिल शूटरों की पहचान हो गई है। चिन्हित शूटरों के घर पर भी छापेमारी की गयी है। पुलिस का दावा है कि अनुसंधान के दौरान ऐसा प्रमाणित हुआ है कि चिन्हित बदमाशों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से बरामद मोबाइल व धनौती नदी के किनारे से बरामद बाइक मालिक को भी चिन्हित कर लिया है, जिसके आधार पर दो बदमाशों की पूरी तरह पहचान हुई है। बताया गया है, कि घटना में प्रयुक्त बरामद काले रंग की आपाची बाइक सुगौली के एक युवक की है। जिसको लेकर उसका बाइक मिस्त्री भाई लक्की निकला था। घटना का सीसीटीवी फुटेज में भी आपाची बाइक लक्की ड्राइव करता दिख रहा है। उक्त फुटेज की पुष्टि भी लक्की के परिजनो ने की है। वहीं घटना स्थल से बरामद मोबाइल अरेराज के राजकुमार पासवान की बताई जा रही है, जिसका डब्बा राजकुमार के घर से बरामद किया गया है, जबकि मोबाइल में लगा सिमकार्ड फर्जी नाम व पते पर निकला है। पुलिस की माने तो चिन्हित दोनों बदमाशों का अबतक कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। लिहाजा ऐसा लग रहा है, कि इन बदमाशो को हत्या के लिए किसी ने सुपारी दी होगी। जिसका खुलासा इन बदमाशो की गिरफ्तारी के बाद ही हो पाएगी। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

अलवर में श्मशान में तीये से पहले कर्मचारी ने कर दी सफाई, अस्थियां नहीं मिलने से परिजन हुए आक्रोशित

अलवर (हिंस)। शहर के प्रताप बंध स्थित शमशान घाट से मृतक महिला की अस्थियों के फूल गायब हो गए। घटना की जानकारी परिजनों को तब मिली जब वह शुक्रवार को तिया करने श्मशान में पहुंचे। घटना से परिजनों में आक्रोश हैं। घटना की सूचना के बाद नगर निगम के सफाई निरिक्षक राकेश शर्मा मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई। उन्होंने माना कि सफाई कर्मचारी से गलती हो गई हैं। सफाई करते वक्त अनभिज्ञता के चलते सफाई कर दी। लेकिन कर्मचारी का ऐसा कोई उदेश्य नहीं था। फिर भी कर्मचारी की लापरवाही को देखते हुए कर्मचारी दीपक को एपीओ कर दिया हैं। परिजन आशीष अग्रवाल ने बताया कि नवाबपुरा मोहल्ला निवासी उनकी नानी मुन्नी देवी का देहांत हो गया था। शुक्रवार को सभी परिजन तीये के लिए श्मशान पहुंचे तो देखा वहां अस्थियों के फूल नहीं हैं। वहां

मिले कर्मचारी से जानकारी जुटाई तो पता चला कर्मचारी ने सफाई कर कूड़े में फेक दिए। इससे परिजन आक्रोशित हो गए और नगर निगम के अधिकारियों को सूचना दी। परिजनों का कहना हैं कि आज अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाना था। ऐसे में अब कैसे जाया जायेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां का सफाई कर्मचारी शराब के नशे में था। उसे होश ही नहीं उसने क्या गलत कर दिया। जबकि कर्मचारी का कहना हैं कि रात बारिश आने से पानी भरा हुआ था जिस कारण पता नहीं चल पाया और गलती से सफाई कर दी थी।

टाटा फिर बना देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड; इंफोसिस नंबर दो तो एचडीएफसी समूह तीसरे नंबर पर

मुंबई।
28.6 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ टाटा समूह एक बार फिर से भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। ब्रांड फाइनेंस ने 2024 की अपनी रिपोर्ट में देश के प्रतिष्ठित टाटा समूह को नंबर एक, सूचना तकनीक क्षेत्र की कंपनी इंफोसिस को नंबर दो और बैंकिंग व फाइनेंस क्षेत्र की एचडीएफसी समूह को तीसरे नंबर पर रखा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा समूह की ब्रांड वैल्यू पिछले साल के मुकाबले इस बार 9 फीसदी बढ़ी है। पहली बार भारत की किसी कंपनी का ब्रांड मूल्य 30 अरब डॉलर के करीब पहुंचा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में लोगों की उम्मीद को दिखाता है। रिपोर्ट के अनुसार इन्फोसिस की ब्रांड वैल्यू में भी 9 फीसदी की वृद्धि हुई है।

खासबात यह है कि पूरी दुनिया में आईटी क्षेत्र में गिरावट के बावजूद इन्फोसिस ने यह उछाल दर्ज की है। उसका ब्रांड मूल्य 14.2 अरब डॉलर है। एचडीएफसी समूह को अपने बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों के एकीकरण का फायदा हुआ है और ब्रांड मूल्यांकन के मामले में 10.4 अरब डॉलर मूल्य के साथ यह तीसरे स्थान पर है। वैसे देश में अन्य बैंकों के ब्रांड मूल्य में भी जोरदार उछाल आया है। इस सेक्टर ने कुल मिलाकर 26 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की है और इसमें भी इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक व यूनियन बैंक का प्रदर्शन जोरदार रहा है।

61 प्रतिशत की दर से टेलीकॉम क्षेत्र की ब्रांड वृद्धि रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक 61 फीसदी की वृद्धि टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों ने दर्ज की है और 26 फीसदी के साथ बैंकिंग दूसरे जबकि खनन, लोहा व इस्पात क्षेत्र ने 16 फीसदी की वृद्धि दर्ज की।

टेलीकॉम क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों जियो, एयरटेल व वीआई ने उपभोक्ताओं के उपभोग पैटर्न को ध्यान में रखकर अपने ग्रोथ को गति दी है। इसी प्रकार बैंकिंग क्षेत्र में नियामकीय सुधार ने ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में मदद की है।

न्यूज ब्रीफ

हेल्थ केयर, फार्मा, इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत इन सेक्टर्स में 6 प्रतिशत बढ़ सकता है रोजगार

नई दिल्ली। भारत के हेल्थ केयर, फार्मा, ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में रोजगार में बढ़त देखने को मिल सकती है। यह जानकारी जारी एक रिपोर्ट में दी गई। स्टाफिंग कंपनी टीमलीज सर्विसेज की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि देश की 23 इंडस्ट्रीज में रोजगार चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीने में 6 प्रतिशत से अधिक दर के साथ बढ़ सकता है। वर्कफोर्स के आकार की वृद्धि के मामले में निर्माण, रियल एस्टेट, ट्रेवल, हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर शीर्ष पर हो सकते हैं। टीमलीज सर्विसेज के सीईओ कार्तिक नारायण ने बताया कि 2024 में जी-20 में भारत सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। मजबूत मांग, निवेश और महंगाई कम होने के कारण जॉब मार्केट में लचीलापन रह सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हर पांच में से दो संस्थाएं स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को प्राथमिकता दे रही है। रोजगार अवसरों के मामले में दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद शीर्ष पर हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जनरेटिव एआई के कारण लोगों को नौकरी पर रखने की स्ट्रेटेजी में बदलाव हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि सर्वे में 56 प्रतिशत नियोक्ताओं का मानना है कि आने वाले दिनों में वे अपनी वर्कफोर्स बढ़ाएंगे, जो दिखाता है कि भारत में नौकरियों को लेकर सकारात्मक रुझान बना हुआ है। नियोक्ताओं की ओर से अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, डिटेल पर निगाह रखने वाले और तकनीक स्किल में सक्षम युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

भारत ने चीन के कई उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया

नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईटीसी) ने चीन तथा कुछ अन्य देशों के कई उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया. बोर्ड के जारी नोटिफिकेशन में इन शुल्कों की घोषणा की गई है। चीन में बने या चीन से निर्यात किये गये सोडियम सायनाइड पर 554 डॉलर प्रति टन तक का और यूरोपीय संघ में बने या वहां से निर्यात सोडियम सायनाइड पर 230 डॉलर प्रति टन, जापान में बने या वहां से निर्यात किये गये सोडियम सायनाइड पर 447 डॉलर और दक्षिण कोरिया में बने या वहां से निर्यात किये गये सोडियम सायनाइड पर 413 डॉलर प्रति टन का डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है। इसी तरह चीन में बने या वहां से निर्यात होने वाले चिजेल टूल और रॉक ब्रेकर्स पर 162.5 प्रतिशत तक और दक्षिण कोरिया में बने या वहां से निर्यात होने वाले चिजेल टूल और रॉक ब्रेकर्स पर 52.77 प्रतिशत तक डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है. चीन में बने या वहां से निर्यात होने वाले टिन प्लेट पर 741 डॉलर प्रति एक लाख पीस का डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है। इस तीनों मामलों में ये शुल्क पांच-पांच साल के लिए लगाये गये हैं. चीन में बने या वहां से निर्यात होने वाले टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर पर 614 डॉलर प्रति टन का डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है. यह छह महीने तक प्रभावी रहेगा। उल्लेखनीय है कि जब किसी देश को लगता है कि कोई दूसरा देश हमारे उद्योग को नुकसान पहुंचाने के लिए लागत से भी कम कीमत पर किसी वस्तु का हमें निर्यात कर रहा है, तो उस पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया जाता है।

जयपुर रग्स ने लंदन में स्टोर खोला

नई दिल्ली । हाथ से कालीन बनाने वाली कंपनी जयपुर रग्स ने लंदन में अपना एक शोरूम खोला है तथा चालू वित्त वर्ष में दो और अंतरराष्ट्रीय स्टोर खोलने की योजना है। जयपुर रग्स ने दिसंबर 2021 में दुनिया की फैशन राजधानी इटली के मिलान में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय स्टोर खोला था। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि हम मिलान और दुबई में अपनी सफलता के बाद वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति का विस्तार करने को लेकर उत्साहित हैं। हम लंदन में अपने नए शोरूम के जरिए वैश्विक ग्राहकों तक भारतीय डिजाइन और शिल्प पहुंचा रहे हैं। यह हमारी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चालू वित्त वर्ष के अंत तक हमारा लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो या उससे अधिक स्टोर खोलना है।

जियो का रिचार्ज 25 प्रतिशत तक महंगा हुआ : 239 वाला प्लान अब 299 में मिलेगा, 3 जुलाई से लागू होंगी नई दरें

मुंबई।
रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स की कीमतें 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत बढ़ा दी हैं। नए टैरिफ प्लान 3 जुलाई से लागू होंगे। अब 239 रुपए वाला सबसे पॉपुलर प्लान 299 रुपए का हो गया है।

239 रुपए वाले प्लान में रोजाना 1.5जीबी डेटा मिलता है। इसकी वैलिडिटी 28 दिनों की होती है। वहीं सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान 155 रुपए का था, यह अब 189 रुपए में मिलेगा।

15 रुपए वाला डेटा ऐड-ऑन अब 19 रुपए का हुआ

मंथली और लॉन्च टर्म रिचार्ज प्लान्स की टैरिफ बढ़ाने के साथ-साथ कंपनी ने डेटा ऐड-ऑन यानी प्लान के दौरान डेटा लिमिट खत्म हो जाने के बाद एक्सट्रा डेटा लेने वाले प्लान्स की कीमतें भी बढ़ाई है। 1जीबी डेटा ऐड ऑन के लिए 15 रुपए लगते थे, उसके लिए अब 19 रुपए देने होंगे।

दिसंबर 2021 में 20 प्रतिशत तक किया था इजाफा

इससे पहले सभी टेलिकॉम कंपनियों ने दिसंबर 2021 में अपने टैरिफ में 20 प्रतिशत से ज्यादा का इजाफा किया था। वहीं, जियो ने 2016 में लॉन्च के बाद पहली बार 2019 में टैरिफ में बढ़ोतरी की थी। जियो ने 2019 में 20-40 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ाए थे।

वीआई और एयरटेल भी बढ़ा सकती हैं कीमतें

अब अनुमान लगाया जा रहा है कि रिलायंस जियो के इस फैसले के बाद देश की दो और टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स वोडाफोन-आइडिया और एयरटेल भी अपने टैरिफ में बढ़ोतरी कर सकती हैं। एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल कई बार इसकी जरूरत पर बोल चुके हैं।

मित्तल ने कई बार कहा है कि दुनियाभर में सबसे सस्ता टैरिफ भारत में है। इसे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को 200 से बढ़ाकर 300 कर किया जा सके।

दो नए एआई-पावर्ड ऐप भी लॉन्च

जियो-सेफ: इसके जरिए कंपनी वॉइस कॉलिंग,

मैसेजिंग, टेक्स्ट, इमेज और फाइल ट्रांसफर की सुविधा देगी। इसके लिए हर महीने 99 रुपए का चार्ज लगेगा।

जियो ट्रांसलेट: यह एक एआई-पावर्ड मल्टी-लिंगुअल कम्युनिकेशन ऐप है। इसके जरिए वॉइस कॉल, मैसेज, टेक्स्ट और इमेज को अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया जा सकेगा। इस सर्विस के लिए भी यूजर्स के हर महीने 99 रुपए देने होंगे।

चौथी तिमाही में एआरपीयू 178.8 बढ़कर 181.7 हुआ

टेलिकॉम कंपनियों के प्रदर्शन को मापने के लिए ऐवरेज रेवेन्यू पर यूजर का इस्तेमाल होता है। एक साल पहले की तुलना में जियो का एआरपीयू 178.8 रुपए से बढ़कर 181.7 रुपए प्रति यूजर प्रति माह हो गया है। जियो ने 1.09 करोड़ सब्सक्राइबर जोड़े।

चौथी तिमाही में मुनाफा 13 प्रतिशत बढ़कर 5,337 करोड़ रहा

वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में रिलायंस जियो का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़कर 5,337 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल समान तिमाही में 4,716 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया था। वहीं तीसरी तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 5,208 करोड़ रहा था। यानी तिमाही आधार पर मुनाफा 2.5 प्रतिशत बढ़ा है।

चौथी तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर 25,959 करोड़ रुपए हो गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये 23,394 करोड़ रुपए रही थी। वहीं पिछली तिमाही में आय 25,368 करोड़ रुपए रही थी। यानी, आय तिमाही आधार पर 2.3 प्रतिशत बढ़ी है।

शेयर व म्यूचुअल फंड परामर्श के लिए सेबी के नए नियम, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के लिए पंजीकरण जरूरी

मुंबई।
सेबी ने फाइनेंशियल इन्फ्लूएंसर्स को लेकर नियम तय कर दिए हैं। अब गैर-पंजीकृत फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए सलाह नहीं दे पाएंगे। निवेशक शिक्षा में इन प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को सेबी के पास पंजीकरण कराना होगा। साथ ही, तय नियमों का पालन भी करना होगा।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की प्रमुख माधबी पुरी बुच ने बृहस्पतिवार को बोर्ड की बैठक के बाद बताया कि म्यूचुअल फंड और शेयर ब्रोकरों के साथ साझेदारी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। विनियमित संस्थाएं यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगी कि जिन व्यक्तियों के साथ वे संबद्ध हैं, वह बाजार नियामक के तय नियमों का पालन करते हैं, जिसमें सुनिश्चित रिटर्न के वादों से बचना भी शामिल है। सेबी ने नए नियम लागू करने से पहले सभी पक्षकारों और उद्योगों से सलाह मांगी थी। उसके बाद ही फाइनेंशियल इन्फ्लूएंसर्स के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया।

तकनीकी गड़बड़ी में एमडी व सीटीओ पर जुर्माना नहीं : कारोबार

डिस्क्लेमर डालकर बचना अब संभव नहीं : दरअसल, फिनफ्लुएंसर्स जवाबदेही से बचने के लिए हर ट्वीट, वीडियो और पोस्ट में डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि वह सेबी से पंजीकृत नहीं हैं। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। सेबी ने साफ किया कि ऐसा करने मात्र से जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। दरअसल, फिनफ्लुएंसर्स गैर-अंग्रेजी भाषी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री बनाते हैं।

भारतीय रेलवे ने बनाया एक और कीर्तिमान, ट्रैक नवीनीकरण में दोहरे अंक में दर्ज की गई वृद्धि

नई दिल्ली।
रेल मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारतीय रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ट्रैक नवीनीकरण में पिछले वर्ष की तुलना में 13.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-2023 में रेलवे ने 5,227 ट्रैक किलोमीटर (टीकेएम) का नवीनीकरण किया। जबकि, 2023-2024 में नवीनीकरण 5,950 टीकेएम तक पहुंच गया।

भारतीय रेलवे आकार के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी परियोजना है। इसके रनिंग ट्रैक की लंबाई 1,04,647 किमी और रूट की लंबाई 68,426 किमी है। 60,451 किमी नेटवर्क विद्युतीकृत है।

1.2 मिलियन से अधिक कर्मचारियों के साथ, रेलवे दुनिया का नौवां सबसे बड़ा कर्मचारियों वाला और भारत में दूसरा सबसे बड़ा कर्मचारियों वाला संस्थान है।

इसके साथ ही बता दें कि भारतीय रेलवे 44,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर अगले 5 वर्षों में सुरक्षा और ट्रेन दुर्घटना से लोगों की रक्षा के

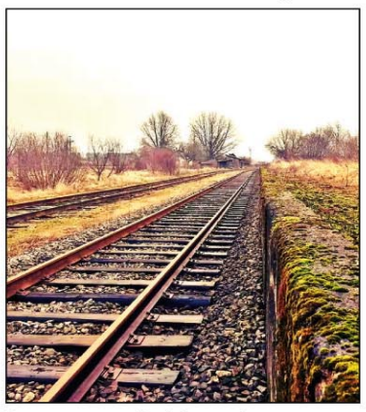

लिए कवच प्रणाली भी तैनात करेगा।

यात्रा के दौरान यात्रियों को सस्ती औषधि मिले, इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर 50 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। जहां लोगों को सस्ती दवाईयां मिल भी रही हैं। वहीं, रेलवे स्टेशनों पर 61 और जन औषधि केंद्र खोलने का काम चल रहा है।

देश की अर्थव्यवस्था मजबूत, बैंकों का कुल एनपीए 12साल के निचले स्तर 2.8 फीसदी पर पहुंचा

मुंबई ।
देश की अर्थव्यवस्था के साथ वित्तीय प्रणाली मजबूत और जुझारू बनी हुई है। बैंकों का सकल एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) अनुपात मार्च, 2024 तक घटकर 12 साल के निचले स्तर 2.8 फीसदी पर आ गया है। वाणिज्यिक बैंकों का शुद्ध एनपीए अनुपात भी कम होकर 0.6 फीसदी के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है।

आरबीआई ने बृहस्पतिवार को जारी जून की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में कहा, 2024-25 अंत तक बैंकों का सकल एनपीए अनुपात और घटकर 2.5 फीसदी पर आ सकता है। अगर वृहद आर्थिक परिवेश गंभीर दबाव परिदृश्य में बिगड़ता है, तो यह अनुपात बढ़कर 3.4 फीसदी तक पहुंच सकता है।

फंसे कर्ज में इसलिएकमी

रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च, 2020 से सकल एनपीए अनुपात में निरंतर कमी मुख्य रूप से नए फंसे कर्ज की वृद्धि में लगातार गिरावट और बट्टे खाते में वृद्धि के कारण हुई है। सकल एनपीए में कमी से बट्टे खाते में डाले जाना वाला अनुपात एक साल पूर्व स्तर पर ही रहा।

सभी तरह के बैंकों में सुधार

रिपोर्ट के मुताबिक, सभी श्रेणी के बैंकों में सकल एनपीए घटा है।सरकारी बैंकों के सकल एनपीए अनुपात में 2023-24 की दूसरी छमाही में 0.76 फीसदी कमी आई।

परिवारों की बचत औसत स्तर से नीचे, देनदारी बढ़ी

परिवारों की बचत 2022-23 में जीडीपी के अनुपात में घटकर 18.4 फीसदी रह गईहै।2013-22 के दौरान इसका औसत अनुपात 20 प्रतिशत था। आरबीआई के मुताबिक, उपरोक्त बचत में शुद्ध वित्तीय बचत 39.8 प्रतिशत से घटकर 28.5 प्रतिशत पर आ गई है। परिवारों की वित्तीय देनदारी भी बढ़ गई है। ब्याज दर आकर्षक होने से वाणिज्यिक बैंको में जमा की रफ्तार 2023-24 में तेज रही। बैंकों ने कर्ज मांग में तेज वृद्धि के अनुरूप धन जुटाने के प्रयास किए। इससे सभी बैंक समूहों में चालू व बचत खाते में जमा बढ़े।

ग्रेनो प्राधिकरण की 12 वाणिज्यिक भूखंडों की योजना लॉन्च, रिजर्व प्राइस 1014 करोड़ रुपये

ग्रेटर नोएडा।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 12 वाणिज्यिक भूखंडों की योजना लॉन्च कर दी है। अगर ये सभी भूखंड आवंटित हो गए तो ग्रेटर नोएडा में जल्द ही 12 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बन सकेंगे।ग्रेटर नोएडा वासियों को रोजमर्रा की जरूरत के सामान खरीदने में और सुविधा हो जाएगी। रिजर्व प्राइस पर इन 12 भूखंडों की कीमत लगभग 1014 करोड़ रुपये है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर वाणिज्यिक विभाग ने 12 भूखंडों की योजना लांच की है।

प्राधिकरण के ओएसडी संतोष कुमार ने बताया कि 26 जून से इस योजना के भूखंडों के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। ये भूखंड 3600 वर्ग मीटर से लेकर 10600

वर्ग मीटर एरिया तक के हैं। ये भूखंड ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 10 में तीन, सेक्टर 12 में पांच, डेल्टा वन में तीन और एक भूखंड सेक्टर 1 में स्थित है।

ओएसडी संतोष कुमार ने बताया कि 26 जून से ब्रोशर डाउनलोड करने की सुविधा शुरू हो गई। स्कीम में पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंट जमा करने की अंतिम तारीख 19 जुलाई है। इन भूखंडों का आवंटन ऑक्शन के जरिए ही किया जाएगा। आवेदन से लेकर आवंटन तक की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी की जाएगी। एसबीआई पोर्टल के जरिए आवेदन किया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट से भी एसबीआई पोर्टल को लिंक किया गया है, ताकि आवेदक प्राधिकरण की वेबसाइट से भी आवेदन कर सकें।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने कहा है कि निवेशकों की मांग और ग्रेटर नोएडा वासियों की जरूरत को देखते हुए प्राधिकरण ने वाणिज्यिक भूखंड योजना को लॉन्च कर दी है। आवंटन प्रक्रिया पूरी होते ही पजेशन दे दिया जाएगा। इन भूखंडों पर वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू होने से आसपास के निवासियों की रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी।

भारत में पिछले तीन वर्षों में चार गुना हुई डिजिटल भुगतान की संख्या

नई दिल्ली। भारत में पिछले तीन वर्षों में मासिक रियल-टाइम भुगतान में चार गुना की बढ़ोतरी हुई है और लेनदेन की संख्या 2.6 अरब से बढ़कर 13.3 अरब हो गई है। बीसीजी-क्यूईडी इन्वेस्टर्स की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि रियल-टाइम पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्टरी और क्यूआर कोड की उपलब्धता इनोवेशन को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट 60 ग्लोबल फिनटेक सीईओ और निवेशकों से मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत की इस उपलब्धि में डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और सरकार की काफी अहम भूमिका है। भारत सरकार की ओर से हाल ही में फिनटेक को केवाईसी और को-लैंडिंग के लिए स्टैंडर्ड का स्पष्टीकरण देने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक इसी प्रकार की गाइडलाइन अमेरिका के कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो की ओर से डोड-फ्रैंक अधिनियम की धारा 1033 के तहत तैयार किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य ग्राहकों को उनके वित्तीय डेटा पर नियंत्रण और इसे एक्सेस और साझा करने का अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाना है। भारत के डीपीआई स्टैक में सरकार द्वारा निर्धारित तीन लेयर्स हैं। जो निजी इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करने के बाद भी फिनटेक इंडस्ट्री में विकास की काफी संभावनाएं हैं।

मीराबाई का लक्ष्य अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ देश को पदक दिलाने का

नई दिल्ली ।
टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने अगले महीने शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ देश को एक और पदक दिलाने का लक्ष्य रखा है। मीराबाई पेरिस ओलंपिक का टिकट पक्का करने वाली भारत की इकलौती भारोत्तोलक है। 49 किग्रा वजन वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाली यह खिलाड़ी पदक के सपने को पूरा करने के लिए चोट से बचने पर ध्यान दे रही है। तीसरी बार ओलंपिक खेलों में भाग लेने की तैयारी कर रही मीराबाई ने साइ (भारतीय खेल प्राधिकरण), आईओसी (भारतीय ओलंपिक संघ) और भारतीय भारोत्तोलक महासंघ (आईडब्ल्यूएलएफ) के सौजन्य से आयोजित ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में पटियाला से कहा, पेरिस को लेकर रोमांचित हूं लेकिन थोड़ी घबराहट और तनाव भी है। पिछले तीन साल (टोक्यो ओलंपिक के बाद) में मेरे काफी प्रतिद्वंद्वी बदल गये हैं। भारत के लिए पदक जीतने का दबाव है लेकिन अगर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल रही तो देश के लिए पदक जीत सकती हूं। मीराबाई चानू का स्नैच में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 88 किग्रा तथा क्लीन एवं जर्क में 119 किग्रा का है। वह चोटों से जूझती रही हैं और पीठ की समस्या तो हमेशा ही रहती है। एशियाई खेलों में वह कूल्हे की चोट से परेशान थीं जिससे वह पांच महीने तक खेल से दूर रहीं। अपने अमेरिकी फिजियो डॉ. आरोन हॉर्शिंग और कोच विजय शर्मा के साथ चोटों से उबरना उनकी बड़ी चुनौती रही है। उन्होंने कहा कि वह धीरे-धीरे वजन उठाने की क्षमता को बढ़ा रही है। मीराबाई ने कहा, मैं धीरे-धीरे वजन उठाने की अपनी क्षमता को बढ़ा रही हूं। अभी मैंने 80-85 प्रतिशत फिटनेस हासिल कर ली है और अभ्यास के दौरान स्नैच में 70 से 80 किग्रा तथा क्लीन एवं जर्क में 100 से 110 किग्रा का भार उठा रही हूं। हम इसे धीरे-धीरे बढ़ाएंगे। उन्होंने अपने भार उठाने के लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर कहा, इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है लेकिन मेरी कोशिश स्नैच में 90 किग्रा और क्लीन एवं जर्क में पहले से बेहतर करने की होगी। मणिपुर की इस खिलाड़ी ने कहा कि अभी उनका पूरा ध्यान चोट से बचने पर है। उन्होंने हॉर्शिंग की तारीफ करते हुए कहा, उनकी मौजूदगी से काफी मदद मिली है। मैं 2020 से उनके साथ काम कर रही हूं और वह अच्छे से समझते है कि मेरे शरीर में कहां परेशानी है। वह जानते है कि चोट से कैसे जल्दी उबरना है और किस तरह से अभ्यास को आगे बढ़ाना है। मीराबाई ने कहा, मैंने चोटिल होने के बाद काफी कुछ सीखा है।

न्यूज ब्रीफ

दुनिया में छाया दिल्ली का लालः कर दिखाया कुछ ऐसा, गर्व से पिता का सीना हुआ चौड़ा; आप भी करेंगे रितेश के जज्बे को सलाम

नई दिल्ली। राजधानी में मजनू के टीले इलाके को ड्रग्स हब के रूप में जाना जाता है। यहां के अधिकतर युवा नशे की लत में लिप्त रहते हैं। लेकिन यहां एक ऐसा भी लड़का रहता है, जो अपने जज्बे, जुनून और कामयाबी की जिद के दम पर विश्वभर में भारत का नाम रोशन कर रहा है। रितेश ने अपने नाम किया श्रेष्ठ लिफ्टर का खिताब बता दें कि हाल ही में जर्मनी के श्वेट्जिंगन में आयोजित आईपीएल यूरोपियन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रितेश डोगरा ने स्वर्णिम प्रदर्शन कर श्रेष्ठ लिफ्टर का खिताब अपने नाम किया। 87 किलो भार वर्ग फुल पावरलिफ्टिंग में रितेश ने कुल 760 किलो भार उठाते हुए दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी स्पर्धा में अमेरिका के जस्टिन 740 किलो और जर्मनी के रवाड 737.5 किलो भार उठाकर क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे। बता दें कि चैंपियनशिप में भारत, जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, व ग्रीस से 121 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। रितेश के पिता चलाते हैं किराने की दुकान रितेश अपने पिता हेमराज डोगरा और मां संतोष डोगरा के साथ मजनू का टीला कॉलोनी के एच-ब्लाक में रहते हैं। उनके पिता किराने की दुकान चलाते हैं और मां गृहिणी हैं। इसी क्रम में गांव ताजपुर निवासी सुरेंद्र सिंह ने फुल पावरलिफ्टिंग रा मास्टर में कुल तीन स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक जीता। सुरेंद्र ने 665 किलो भार उठाया। जर्मनी के मिशेल 650 किलो दूसरे और जर्मनी के ही ल्यूकास 645 किलो भार उठाकर तीसरे स्थान पर रहे। द्रोणाचार्य अवार्डी भूपेंद्र धवन के शिष्य हैं तीनों वहीं मुखर्जी नगर निवासी फुल पावरलिफ्टिंग ओपन रा में प्रभजीत बख्शी ने दो स्वर्ण और एक रजत जीता। प्रभजीत ने कुल 690 किलो भार उठाया। दूसरे स्थान पर सुरेंद्र सिंह ने 665 किलो भार उठाया और तीसरे स्थान पर ग्रीस के चारिडिमास ने कुल 655 किलो भार उठाया। बता दें कि यह तीनों ही द्रोणाचार्य अवार्डी भूपेंद्र धवन के शिष्य हैं। रितेश की उपलब्धियां - वर्ष 2023 में फ्लोरिडा स्थित आरलैंडो में प्रो ओलिंपिया पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में दो स्वर्ण और एक रजत - वर्ष 2014 में आगरा में जूनियर राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक - वर्ष 2015 में सीनियर राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण - साल 2015 के अंत में ओपन अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग में स्वर्ण के रूप में पहला अंतरराष्ट्रीय पदक - साल 2017 में विश्व पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में तीन स्वर्ण पदक।

लंदन में होगा वैश्विक शतरंज लीग का आयोजन, एफआईडीई के अध्यक्ष ने की पुष्टि

नई दिल्ली । यह लीग टीम आधारित प्रारूप में खेली जाएगी जिसमें मौजूदा विश्व चैंपियन सहित कई युवा खिलाड़ी भी भाग लेंगे। प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होंगे, जिनमें दो शीर्ष महिला खिलाड़ी और एक उभरता हुआ खिलाड़ी शामिल हैं। दूसरी वैश्विक शतरंज लीग का आयोजन तीन से 12 अक्टूबर तक लंदन में किया जाएगा। आयोजकों ने यह जानकारी दी। वैश्विक शतरंज लीग अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (एफआईडीई) और टेक महिंद्रा की संयुक्त पहल है। दस दिन तक चलने वाली इस लीग का आयोजन सेंट्रल लंदन के फ्रेंड्स हाउस में किया जाएगा जिसमें दुनिया के चोटी के खिलाड़ी भाग लेंगे। एफआईडीई के अध्यक्ष अर्कडी ड्वोर्कोविच ने बयान में कहा, इस प्रतियोगिता के पहले सत्र को मिली अपार सफलता के बाद हम शतरंज का दुनिया भर में विस्तार करने और शतरंज प्रेमियों को नया अनुभव दिलाने के अपने मिशन को आगे बढ़ाने को लेकर उत्साहित हैं।

जर्मनी की महिलाओं ने हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई किया

नई दिल्ली । एफआईएच हॉकी प्रो लीग के 2023/24 सीज़न की शुरुआत में, इस आयोजन में एक नया प्रोत्साहन जोड़ा गया, जिसमें खिताब विजेता आगामी एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 के लिए सीधे योग्यता अर्जित करेंगे। नियमों के अनुसार, बेल्जियम या नीदरलैंड पुरुष या महिला दोनों में से किसी एक का खिताब जीतते हैं, तो उनके पीछे सर्वोच्च स्थान पर रहने वाली टीम विश्व कप के लिए क्वालीफाइंग में अपना स्थान ले लेगी। नीदरलैंड की महिलाएं एफआईएच हॉकी प्रो लीग के पूरे सीजन में शानदार फॉर्म में रही हैं और 22 जून को जर्मनी के खिलाफ 4-0 से जीत के साथ अपने घरेलू दर्शकों के सामने अपना लगातार दूसरा, कुल मिलाकर चौथा खिताब जीता। मेजबान के रूप में, नीदरलैंड ने पहले ही आगामी विश्व कप के लिए योग्यता हासिल कर ली थी, इसलिए प्रो लीग में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को हॉकी के शोपीस चतुष्कोणीय आयोजन में सीधे योग्यता स्थान प्राप्त होगा।

रोहित 49 जीत के साथ टी-20 के सबसे सफल कप्तान : इस फॉर्मेट में उनके नाम सबसे ज्यादा चौके, कोहली सबसे ज्यादा सिंगल डिजिट पर आउट

नई दिल्ली ।
भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। टीम तीसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। टीम इंडिया ने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 68 रनों से हराया। इसी के साथ रोहित शर्मा 49 मैच जीतकर दुनिया के सबसे सफल टी-20 कप्तान बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम (48 जीत) को पीछे छोड़ा।

गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन का स्कोर बनाया, फिर इंग्लिश टीम को 16.4 ओवर में 103 रन पर ऑलआउट कर दिया।

इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 39 बॉल पर 57 रनों की पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के जमाए। रोहित ने 146.15 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। रोहित टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इतना ही नहीं, वे आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मैच के टॉप सिक्स हिटर भी बन गए हैं। वहीं, विराट कोहली टी-20 वर्ल्ड कप के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा बार सिंगल डिजिट पर आउट होने वाले भारतीय बैटर बनने का अनचाहा रिकॉर्ड बनाया है।

कुछ अहम रिकॉर्ड...

1. टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके लगाए - भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतकीय पारी में 4 चौके लगाए। वे टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित के नाम 113 चौके हो गए हैं। उन्होंने पूर्व श्रीलंकाई बल्लेबाज महेला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ा। जयवर्धने के नाम इस टूर्नामेंट में 111 चौके हैं। इस सूची में तीसरा नाम विराट कोहली का है। कोहली टी-20 वर्ल्ड कप में 105 चौके लगा चुके हैं।

2. आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मैच में सबसे ज्यादा सिक्स लगाए - रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में 2 छक्के लगाए। वे आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने 13वां ओवर डाल रहे सैम करन की तीसरी बॉल पर सिक्स लगाया। रोहित के नाम अब 22 सिक्स हो चुके हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के 21 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा।

3. 5 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले 5वें भारतीय कप्तान - रोहित शर्मा 5 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले 5वें भारतीय कप्तान बने हैं। रोहित से पहले विराट कोहली, एमएस धोनी, मोहम्मद अजहर, सौरव गांगुली अपनी कप्तानी में 5 हजार से ज्यादा रन बना चुके हैं। रोहित आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट के टॉप-2 स्कोरर बने हैं। रोहित के नाम 771 रन हो गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग (731 रन) को पीछे छोड़ा।

4. टी-20 वर्ल्ड कप में कोहली के बाद टॉप स्कोरर - रोहित शर्मा टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं। कोहली 1216 रन बना चुके हैं, जबकि रोहित ने 1211 रन बनाए हैं। रोहित ने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर महेला जयवर्धने को पीछे छोड़ा है। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर भी एक हजार रन पूरे कर चुके हैं।

5. एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार सिंगल डिजिट पर आउट कोहली - विराट कोहली टी-20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा बार सिंगल डिजिट पर आउट होने वाले भारतीय बैटर बने हैं। वे मौजूदा वर्ल्ड कप में 5 बार सिंगल डिजिट पर आउट हो चुके हैं। कोहली से पहले केएल राहुल 2022 के सीजन में 4 बार सिंगल डिजिट पर आउट हुए थे।

6. टी-20 वर्ल्डकप सेमीफाइनल में पहली बार सिंगल डिजिट पर आउट - विराट कोहली टी-20 वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में पहली बार सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 9 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले कोहली ने 2014 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 72, 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 89 और 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 50 रन बनाए थे।

7. रॉड टकर ने सबसे ज्यादा टी-20 वर्ल्डकप मैच में अंपायरिंग की - ऑस्ट्रेलिया के रॉड टकर सबसे ज्यादा टी-20 वर्ल्ड कप मैचों में अंपायरिंग करने वाले अंपायर बने हैं। उन्होंने 46 मैचों में अंपायरिंग की है। उन्होंने पाकिस्तान के अलीम डाल के 45 मैचों का रिकॉर्ड तोड़ा।

8. 13वीं बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत, ऑस्ट्रेलिया की बराबरी की - भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली टीम के रिकॉर्ड की बराबरी की है। टीम इंडिया 13 आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड की बराबरी की है।

9. भारत तीसरी बार टी-20 के फाइनल में; इंग्लैंड, श्रीलंका और इंग्लैंड के बराबर - टीम इंडिया तीसरी बार टी-20 वर्ल्डकप के फाइनल में पहुंची है। टीम ने श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड के रिकॉर्ड की बराबरी की है। इन सभी टीमों ने 3-3 दफा इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला है।

भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश की क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत, इस खिलाड़ी को दी मात

नई दिल्ली ।
भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सुपरबेट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट के पहले दौर में जीत हासिल कर विजयी शुरुआत की। गुकेश ने रोमानिया के डेक बोगडान-डैनियल को हराया। इस साल के आखिर में मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को चुनौती देने को तैयार गुकेश को इस मुकाबले के दौरान किस्मत का भी साथ मिला, जब उनकी गलती पर रोमानिया का खिलाड़ी फायदा उठाने में नाकाम रहा। गुकेश ने इसके बाद शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की।

बोगडान-डैनियल ने निम्जो इंडियन डिफेंस चाल से शुरुआत की जिसने मुकाबला बीच में जटिल बना दिया। रोमानिया के खिलाड़ी के पास गुकेश पर बढ़त बनाने का मौका था, लेकिन उन्होंने प्यादे के मुकाबले अपने 'रूक (हाथी)' को गंवा दिया। गुकेश इसके बाद मजबूत वापसी करने में सफल रहे। उन्होंने विरोधी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं देते हुए जीत दर्ज की। गुकेश कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने के बाद पहली बार क्लासिकल शतरंज की किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं।

प्रज्ञानंद को अब्दुसात्तोरोव से मिली चुनौती

इस टूर्नामेंट में चुनौती पेश कर रहे एक अन्य भारतीय आर प्रज्ञानंद ने कड़ी मेहनत की, लेकिन उन्हें उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसात्तोरोव के खिलाफ कड़े मुकाबले में ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। काले मोहरों से खेल रहे प्रज्ञानंद को अब्दुसात्तोरोव से कड़ी चुनौती मिली। दोनों खिलाड़ी 60 चालों के बाद बराबरी पर सहमत हो गए। अमेरिका के फैबियानो कारुआना भी शुरुआती दौर में जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ियों में शामिल रहे। उन्होंने फ्रांस के फिरोजा अलीरेजा को हराया। 10 खिलाड़ियों के राउंड-रोबिन टूर्नामेंट में अन्य दो मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए।

इस टूर्नामेंट से हमें काफी कुछ सीखने को मिला : राशिद

तारोबा ।
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान ने कहा है कि उनकी टीम टी20 विश्वकप सेमीफाइनल में हारी जरुर है पर उनका हौंसला नहीं टूटा है। राशिद ने कहा कि यह उनकी टीम के लिए शुरूआत है। इस टूर्नामेंट से खिलाड़ी को काफी अनुभव मिला है। इसके अलावा उन्हें ये भी भरोसा हुआ है कि वे किसी भी टीम को हरा सकते हैं। इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों को हराकर उलटफेर करने वाली अफगानिस्तान टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले सेमीफाइनल में करारी हार का सामना करना पड़ा है।

राशिद ने इसी को लेकर कहा, 'एक टीम के रूप में हमारे लिए इस प्रकार का प्रदर्शन स्वीकार करना कठिन था। हम इस मैच में भी बेहतर प्रदर्शन करते पर हालात ने हमारा साथ नहीं दिया। टी20 क्रिकेट यही है जिसमें आपको हर प्रकार के हालात के अनुरूप ढलना होता है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा, 'हमारे लिए यह शुरूआत भर है। हमारे अंदर किसी भी टीम को हराने का आत्मविश्वास आ रहा है। हमें प्रक्रिया पर ध्यान देना है। हमने यहां से बहुत कुछ सीखा है।

राशिद ने कहा, 'इस टूर्नामेंट से हम आत्मविश्वास लेकर जा रहे हैं। हमें पता है कि हमारे पास कौशल है हमने यहां हमने कठिन और दबाव भरे हालात में खेलना सीखा। एक टीम के रूप में किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है, यह पूछने पर राशिद ने कहा, 'कुछ सुधार तो करना होगा। खासकर मध्यक्रम की बल्लेबाजी में ये जरुरी है। अभी तक परिणाम अच्छे रहे हैं पर हमें बल्लेबाजी में और मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा, 'दक्षिण अफ्रीकी टीम ने इस मैच में शानदार गेंदबाजी की। हमें अपने गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन के दम पर टूर्नामेंट में अधिक मिली हालांकि बल्लेबाजों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा।

पंजाब हॉकी लीग का उद्घाटन सत्र 29 जून से

मोहाली।
पंजाब हॉकी लीग (पीएचएल) का उद्घाटन सत्र जूनियर आयु वर्ग कार्यक्रम के साथ शुरू होगा। राज्य की विभिन्न टीमों का प्रतिनिधित्व करने वाली छह टीमें लीग के इस संस्करण में भाग लेंगी, जो होम-एंड-अवे मैच प्रारूप का अनुसरण करती है। हॉकी पंजाब के सहयोग से राउंडग्लास द्वारा आयोजित इस लीग का उद्देश्य जमीनी स्तर के खिलाड़ियों को मूल्यवान मैच अनुभव प्रदान करना, उनके पेशेवर और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना है।

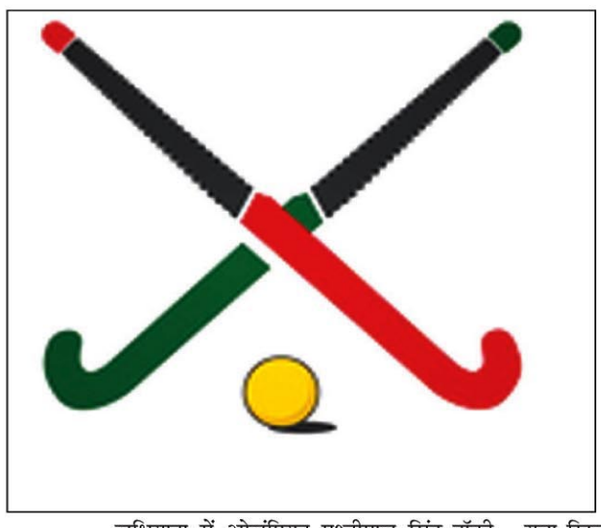

मैच प्रमुख स्थानों जैसे जालंधर में ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम, मोहाली में बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, लुधियाना में ओलंपियन पृथ्वीपाल सिंह हॉकी स्टेडियम और नामधारी हॉकी स्टेडियम, जीवन नगर में होने वाले हैं। प्रत्येक मैच की मेजबानी भाग लेने वाली टीमों में से एक द्वारा की जाएगी।

लीग का उद्घाटन मैच जालंधर के ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम में सुरजीत हॉकी अकादमी पीआईएस, जालंधर और नामधारी स्पोर्ट्स अकादमी के बीच खेला जाएगा, जिसके बाद एस.जी.पी.सी हॉकी अकादमी, अमृतसर का मुकाबला पीआईएस मोहाली से होगा। पीआईएस लुधियाना और राउंडग्लास हॉकी अकादमी लीग में भाग लेने वाली अन्य दो टीमें हैं।

मैच सप्ताहांत के दौरान खेले जाएंगे और 25 अगस्त तक चलेंगे, जिसमें राउंडग्लास हॉकी अकादमी और सुरजीत हॉकी अकादमी पीआईएस जालंधर के बीच अंतिम लीग मैच होगा। प्रत्येक टीम में 25 खिलाड़ियों का पूल होगा।

लीग में 5.5 लाख रुपये का पुरस्कार पूल होगा जो जूनियर हॉकी लीग के लिए सबसे अधिक में से एक है।

पंजाब हॉकी लीग पर अपने विचार साझा करते हुए, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और राउंडग्लास हॉकी अकादमी के तकनीकी प्रमुख, राजिंदर सिंह ने कहा, युवा खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिस्पर्धी मैचों का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है और जूनियर पंजाब हॉकी लीग का उद्देश्य यही है। लीग प्रारूप कोचों को विभिन्न रणनीतियों के साथ प्रयोग करने में मदद करेगा क्योंकि प्रत्येक टीम को 10 मैच खेलने का आश्वासन दिया गया है। हमें उम्मीद है कि यह लीग पंजाब में जमीनी स्तर पर हॉकी को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों में एक ऐतिहासिक आयोजन होगा।

लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क को आधुनिक स्पोर्ट्स जोन बनाने तैयारी में योगी सरकार, 10.16 करोड़ रुपए की लागत से होंगे विकास कार्य

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्प योगी सरकार ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क के वृहद कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लखनऊ के गोमती नगर में स्थित इस पार्क में लंबे वक्त से एक स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स एरीना होने की कमी यहां जाने वाले लोगों को महसूस होती थी।

इस जरूरत को भांपते हुए योगी सरकार ने पार्क के कायाकल्प की एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की थी। सीएम योगी के विजन अनुसार बनी इस कार्ययोजना को क्रियान्वित करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने स्पोर्ट्स जोन के विकास के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। कार्ययोजना के अनुसार, 10.16 करोड़ रुपए के व्यय से सभी विकास कार्यों को पूर्ण किया जाएगा।

टेनिस कोर्ट का भी होगा निर्माण

खास बात ये है कि इन विकास कार्यों के जरिए जिन स्पोर्ट्स एमिनिटीज से पार्क को लैस किया जाएगा उनमें क्रिकेट, फुटबॉल व वॉलीबॉल ग्राउंड समेत टेनिस कोर्ट मुख्य है। इन सभी निर्माण कार्यों को पर्यावरण संरक्षण के मानकों व अन्य महत्वपूर्ण गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूरा किया जाएगा तथा सभी निर्माणों की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए भी एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा।

टू बिड प्रक्रिया के जरिए एजेंसी का होगा चयन

पार्क में स्पोर्ट्स जोने के विकास को लेकर होने वाले सभी कार्यों को पूरा करने के लिए एलडीए द्वारा टू बिड प्रक्रिया को क्रियान्वित किया गया है। इस प्रक्रिया के जरिए एक एजेंसी का चयन होगा और वह ही इन सभी कार्यों को पूर्ण करने के साथ ही एलडीए के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्यों की डेडलाइन, उच्च गुणवत्ता समेत सभी मानकों के पालन व क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेगी। कार्यावंटन के उपरांत एजेंसी की कोशिश होगी कि सभी विकास कार्यों को 9 महीने की अवधि में पूरा कर लिया जाए।

कई खेल गतिविधियों का हो सकेगा संचालन

168 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 376 एकड़ में विकसित किया गया पार्क में लंबे वक्त से स्पोर्टिंग इवेंट्स के संचालन के लिए एक स्पोर्ट एरीना की कमी महसूस हो रही थी। अब इसी कमी को पूरा करते हुए योगी सरकार के विजन अनुसार वृहद स्पोर्ट्स जोन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

एलडीए द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर लखनऊ वासियों तथा देश-विदेश से पार्क घूमने आने वाले लोगों को विभिन्न स्पोर्टिंग इवेंट्स का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। विकास कार्यों की पूर्ति के जरिए यहां पर नियमित रूप से विभिन्न स्पोर्टिंग एक्टिविटीज के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। विकसित होने वाले सभी स्पोर्ट्स एमिनिटीज को आधुनिक स्प्रिंकलर्स, लाइटिंग व अन्य सुविधाओं से पूर्ण किया जाएगा।

डिप्रेशन से डरें नहीं

जिंदगी हमें तरह-तरह के रंग दिखाती है। इसमें हमें कभी खुशियों की सौगात मिलती है, तो कभी दुख का अहसास भी होता है। कई बार हमारे जीवन का दुख काफी लंबा हो जाता है जो, डिप्रेशन यानी अवसाद का कारण बन सकता है। यह जीवन पर पडने वाला ऐसा काला साया है, जिससे जीवन के प्रति रुचि खत्म होने लगती है और दिन-प्रतिदिन के कामकाज से भी मन उचट जाता है, लेकिन अब इस मनोरोग से छुटकारा संभव है... डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के निजी जीवन से जुड़ी कई बातें भी डिप्रेशन केलिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे हमारे जीवन में आने वाले महत्वपूर्ण पड़ाव जिसमें किसी प्रियजन का बिछडना, नौकरी का छूट जाना, विवाह संबंधों में टूटन, शिक्षा के क्षेत्र में असफलता और इस तरह की अन्य समस्याएं अवसाद का कारण बनती हैं। इसके अलावा जीवन के प्रति नकारात्मक सोच रखने वाले लोग अवसाद या डिप्रेशन से कहीं ज्यादा ग्रस्त होते हैं। जैसे वे सोचते हैं कि मैं सफल नहीं होऊंगा, इसलिए यह कार्य नहीं कर सकता या फिर कई लोगों के मन में हमेशा कुछ न कुछ अनहोनी का डर बना रहता है जिससे उनके अवसाद में जाने का खतरा बना रहता है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जिनके कारण व्यक्ति अवसाद में जा सकता है। जैसे थायराइड से संबंधित बीमारियां, विटामिन डी की कमी और पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं आदि। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स के कारण भी व्यक्ति डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच सकता है।

उदासी या एकाकीपन

अगर व्यक्ति डिप्रेशन या अवसाद से ग्रस्त है, तो उसका किसी काम या विषय में मन नहीं लगता। हालांकि सामान्य उदासी अवसादग्रस्त उदासी से बिल्कुल भिन्न है। अवसादग्रस्त व्यक्ति की विभिन्न वस्तुओं या विषयों से रुचि खत्म हो जाती है, उसे खुशी या गम का अहसास नहीं होता। वह अपनी ही दुनिया में खोया रहता है।

नकारात्मक रवैया: किसी भी तरह की सकारात्मक सोच पर ये लोग ध्यान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति पर नकारात्मक सोच हावी रहती है।

शारीरिक अस्थिरता

अगर व्यक्ति अवसादग्रस्त है, तो उसे या तो अत्यधिक नींद आती है या फिर नींद कम आती है। कई बार आधी रात को ही नींद खुल जाती है। अवसादग्रस्त व्यक्ति को भूख कम लगती है और उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। अवसाद आनुवांशिक कारणों से भी संभव है। अवसाद किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। अवसाद के भी विभिन्न स्तर हैं, जो इस प्रकार हैं- मेजर, क्रॉनिक, मैनिएक और अन्य प्रकार के अवसाद।

मेजर डिप्रेशन

एक गंभीर समस्या डिप्रेशन का सबसे सामान्य रूप है- मेजर डिप्रेशन। इसके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं...

- पीड़ित व्यक्ति अत्यधिक दुख, हताशा, ऊर्जा की कमी और चिड़चिड़ापन महसूस करता है।
- किसी काम में ध्यान न लगना। नींद और खाने की आदतों में परिवर्तन।
- शारीरिक दर्द और आत्महत्या जैसे विचारों का अहसास।

इलाज: मेजर डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति कम से कम दो हफ्ते से ज्यादा समय तक अगर उपर्युक्त लक्षणों से ग्रस्त हैं, तो उसके परिजनों को मनोचिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। अच्छी बात यह है कि मेजर डिप्रेशन की चपेट में आने वाले 80 से 90 प्रतिशत व्यक्ति उचित इलाज

से ठीक हो जाते हैं। इलाज के अंतर्गत दवाएं और मरीज के साथ ही उसके परिजनों की काउंसलिंग की जाती है। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी (मरीज के सोचने के ढंग को बदलने के लिए प्रेरित करना) भी दी जाती है।

बाइपोलर डिसऑर्डर

बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनिएक डिप्रेशन भी कहा जाता है, जो मानसिक चंचलता और मानसिक दिक्कतों का कारण बनता है। जब व्यक्ति अवसादग्रस्त होता है, तब वह दुखी या हताश महसूस करता है और किसी भी क्रियाकलाप के प्रति दिलचस्पी खो देता है, लेकिन जब उसका मूड दूसरी दिशा में शिफ्ट होता है, तब वह ऊर्जा से भरपूर और उल्लासमय नजर आता है। मूड का इस तरह बदलना जीवन में कई बार हो सकता है। कुछ लोगों में यह बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। **इलाज:** विशेषज्ञ की सलाह पर ट्रीटमेंट लेना आवश्यक है। ज्यादातर मामलों में बाइपोलर डिसऑर्डर को दवाओं और काउंसलिंग के जरिएनियंत्रित किया जा सकता है।

अल्जाइमर से भूली बातें वापस आ सकती हैं याद

अल्जाइमर के कारण लोग बातें भूल जाते हैं। उन्हें याद दिलाना जटिल काम है। लेकिन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सुसुमु तोनेगावा ने अपने नए शोध के आधार पर पाया है कि दिमाग के एक खास हिस्से में नीली रोशनी डालने से याददाश्त वापस लाई जा सकती है। जापानी वैज्ञानिक सुसुमु को जेनेटिक मैकेनिज्म में उनकी खोज के लिए 1987 में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वे मोल्येकुलर (आणविक) जीवविज्ञानी हैं। लेकिन उन्हें इम्यूनोलॉजी (रोगक्षमता विज्ञान) में काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब वे न्यूरोसाइंस (तंत्रिका विज्ञान) के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सुसुमु की टीम ने अभी चूहे तक ही प्रयोग किया है और वे सफल रहे हैं। उनका कहना है कि याददाश्त के मामले में चूहे और आदमी में एक समान चीजें पाई जाती हैं इसलिए यह संभावना बनी है। अल्जाइमर के शुरुआती स्टेज में तो इसकी संभावना ज्यादा है कि याददाश्त वापस लाई जाए। इस प्रयोग के बारे में 'नेचर' जर्नल में इस टीम का लेख छपा है।

कैसे किया

इसके लिए चूहे में जेनेटिक बदलाव लाया गया ताकि उसके दिमाग में उस तरह की स्थिति लाई जा सके जो अल्जाइमर की शुरुआत में होती हैं। ऐसे कई चूहों को एक बक्से में रखा गया जिसके पेंदे में काफी कम स्तर का बिजली का करेंट दिया गया। यह उनके लिए असुविधाजनक तो था लेकिन खतरनाक नहीं था। इसका मकसद उनके पैरों को शॉक ट्रीटमेंट देना था। थोड़े दिनों बाद दिमाग की स्कैनिंग से लगा कि वे कुछ बातें भूल गए हो सकते हैं। फिर, उन चूहों के सिर के एक खास हिस्से को लेजर से नीली रोशनी डालकर उत्तेजित किया गया। इस हिस्से को 'एनग्राम सेल्स' कहते हैं। इससे उन्हें उस शॉक की याद आने लगी।

क्या संभावनाएं हैं

सामान्य चूहे पर भी इसी तरह के प्रयोग किए गए। इसका मकसद यह देखना था कि उनके दिमाग पर वही असर होता है या वे सामान्य तरीके से व्यवहार करते हैं। सामान्य तरीके का व्यवहार पाए जाने के बाद यह पाया गया कि अल्जाइमर का इस तरह इलाज किया जाना संभव है। चूंकि इसमें ऑप्टिकल (प्रकाशीय) तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है इसलिए इसे ऑप्टोजेनेटिक्स नाम दिया गया है। आने वाले दिनों में इस तरह के प्रयोग लोगों पर भी किए जाएंगे।

चेहरे के अनचाहे बालों से ऐसे पाएं छुटकारा

चेहरे के अनचाहे बाल खूबसूरती में दाग की तरह होते हैं, इनके कारण आपको परेशानी हो सकती है। चेहरे के इन बालों को हटाने के लिए आप कई कोशिशें करते हैं लेकिन फिर से ये बाल आपके चेहरे पर उग जाते हैं। अनचाहे बाल किसी शारीरिक कमी के कारण नहीं बल्कि हार्मोंस असंतुलन के कारण आते हैं। अगर आपके चेहरे पर भी अनचाहे बाल हैं तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ आसान तरीकों को आजमाकर आप इन से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं।

वैक्सिंग के जरिए

यह चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने का बहुत ही आसान तरीका है, इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। वैक्सिंग के द्वारा चेहरे के किसी भी हिस्से में मौजूद बालों को हटाया जा सकता है। इससे अनचाहे बाल पूरी तरह साफ हो जाते हैं और आपके चेहरे की त्वचा मुलायम हो जाती है। चेहरे के बाल हटाने के लिए कटोरी वैक्सिंग की जाती है। वैक्सिंग के बाद बाल लंबे समय तक दोबारा नहीं आते, क्योंकि यह चेहरे की त्वचा के अंदर जड़ों से बालों को निकालता है।

ब्लीचिंग के द्वारा

अगर आपके चेहरे और कनपटियों के आसपास हल्के-हल्के रोएं दिखाई देते हैं तो उन्हें छिपाने के लिए ब्लीचिंग कर सकती हैं। लेकिन ब्लीचिंग करने से पहले अपनी त्वचा के प्रकार को ध्यान में रखें, यह भी देख लीजिए कि क्या यह आपकी त्वचा को सूट भी कर रहा है या नहीं। इसके लिए तैयार की हुई ब्लीच को अपनी हथेली पर लगाकर देखिए, इसके बाद ही इसका प्रयोग करें। ब्लीचिंग करने से पहले एक बात और ध्यान रखें यह रोएं हटाने का स्थाई उपचार नहीं है बल्कि यह तरीका आपको समय-समय पर दोहराना पड़ेगा।

थ्रेडिंग और ट्वीजिंग से

चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए थ्रेडिंग और ट्वीजिंग का प्रयोग कीजिए। चेहरे के अनचाहे बाल ज्यादातर अनचाहे बाल ठोड़ी, होंठों के उपर और कपोल पर ही होते हैं। थ्रेडिंग के जरिए चेहरे के अनचाहे बालों से छुटकारा मिल सकता है। ये भी यह वैक्सिंग की तरह अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आईब्रो को सही

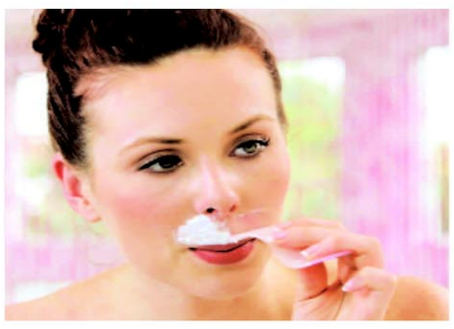

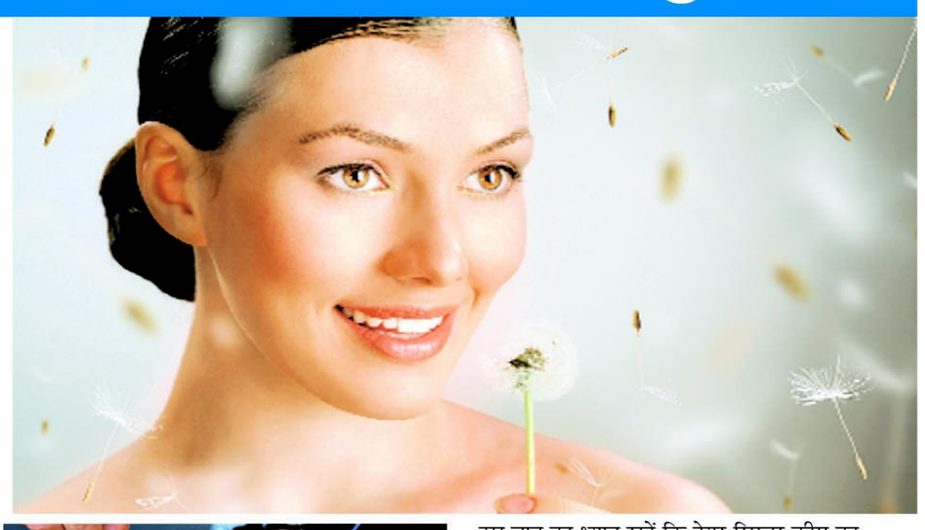

आकार देने के लिए भी थ्रेडिंग की जाती है। इन बालों को कैंची से नहीं काटना चाहिए क्योंकि यह स्थाई उपचार नहीं हैं। ठोड़ी पर आए अनचाहे बालों को आप प्लकिंग करके भी निकाल सकते हैं, इसके लिए आइब्रो-ट्वीजर चिमटी का प्रयोग बेहतर माना जाता है।

हेयर रिमूविंग क्रीम

चेहरे के बालों को हटाने के लिए हेयर रिमूवर क्रीम का प्रयोग कीजिए। इससे अनचाहे बालों को हटाने में कोई दर्द नहीं होता और न ही ज्यादा समय लगता है। लेकिन इसका प्रयोग करने का सबसे ज्यादा नुकसान यह है कि इससे अनचाहे बाल दोबारा जल्दी उग आते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि हेयर रिमूवर क्रीम का इस्तेमाल कभी भी अपने चेहरे पर न करें।

इलेक्ट्रोलिसिस

होंठों के ऊपर आने वाले बालों के लिए प्लकिंग न करते हुए इलेक्ट्रोलिसिस का प्रयोग अच्छा माना जाता है। हालांकि इस तकनीक से आप शरीर के अन्य हिस्सों के बाल भी हटा सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान बिजली के हल्के करंट का प्रयोग किया जाता हैं। लेकिन इस तकनीक के प्रयोग के लिए आपको कुछ हफ्तों तक इसका प्रयोग करना आवश्यक है तभी आप स्थाई रूप से अनचाहे बालों से मुक्ति मिल सकती है।

लेजर तकनीक

लेजर से चेहरे के अनचाहे बालों को स्थाई रूप से हटाया जा सकता है क्योंकि लेजर से बालों को हमेशा के लिए जड़ से खत्म किया जाता है। लेजर की किरणों को बालों की जड़ पर केंद्रित किया जाता है, जिससे बाल हमेंशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इसमें लगभग सात से 8 सिटिंग्स लगती हैं।

इसके अलावा चेहरे के बालों को हटाने के लिए आप घरेलू नुस्खों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कोई भी तरीका आजमाने से पहले अपने चेहरे की संवेदनशीलता को जरूर मापें। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।

बौनेपन का इलाज संभव

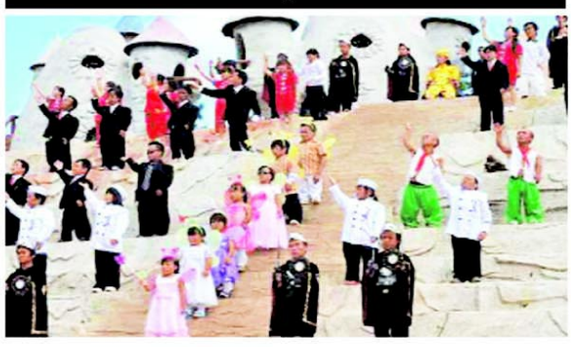

बौनापन भी अब लाइलाज नहीं रहा। ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन लगाकर इसका ट्रीटमेंट संभव है... जब लंबाई 147 सेमी. से कम हो तो उसे बौना व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन हर बौने व्यक्ति के शरीर के लक्षण एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। बौने व्यक्ति के शरीर के सभी भागों की लंबाई, असंगत (डिस्प्रोपोशनेट) होती है, हाथ लंबे होते हैं, पैर छोटे होते, पैर बड़े हो तो हाथ छोटे होते हैं। पेट व छाती की बनावट भिन्न होती है। इस तरह की बनावट में शरीर के अंगों में सामंजस्यता नहीं पाई जाती है। संगत (प्रपोशनेट) बौनापन में शरीर के सभी अंग सामान्य से छोटे होते हैं।

बौनेपन के प्रकार

शरीर के अंगों की लम्बाई व बनावट के आधार पर इनका वर्गीकरण निम्न वर्गों में किया गया है।

- **रोजोमेलिक:** इस तरह के बौने व्यक्तियों में बाजू और जांघ बहुत छोटे होते हैं। बाकी शरीर सामान्य होता है।
- **मिजोमेलिक:** इनमें बाजू के अग्र भाग और पैरों की लम्बाई सामान्य से बहुत कम होती है। बाकी शरीर सामान्य होता है।
- **एक्रोमेलिक:** जब पैर व हाथ दोनों ही बहुत ज्यादा छोटे होते हैं बाकि शरीर की लम्बाई सामान्य होती है।
- **माइक्रोमेलिक:** जब हाथ व पैरों की लम्बाई सामान्य से बहुत कम होती है।

कारण: शरीर से जुड़ी 300 तरह की बीमारियों में से कोई एक बौनेपन का कारण होती है लेकिन इससे ग्रसित 70 प्रतिशत व्यक्तियों में बौनेपन की वजह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित ग्रोथ हार्मोन का न बनना होता है। दूसरा मुख्य कारण जिसे एकोण्ड्रोप्लेजिया कहते हैं इसमें शरीर के जोड़ों में असमानता व लचीलापन होता है। यह समस्या आनुवांशिक होती है। इसमें एफजीएफआर-3 नामक जीन में बदलाव से हड्डियों की वृद्धि नहीं होने के कारण बौनापन हो जाता है।

उपचार: एक साल की उम्र तक बच्चे का उचित विकास न हो तो माता-पिता को एंडोक्रायोनोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से संपर्क करें। विशेषज्ञ बच्चे को तीन साल तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद बौनेपन के बारे में निर्णय लेते हैं। 5-7 साल की उम्र में ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हर तीन माह में रक्त जांच करके हार्मोंस वृद्धि का पता लगाया जाता है। यदि नतीजे पॉजिटिव होते हैं तो दोबारा इंजेक्शन लगाया जाता है। यह प्रक्रिया 13-15 साल की उम्र तक चलती है। रक्त में ग्रोथ हार्मोन की सामान्य मात्रा औसतन 4-17 माइक्रोमिलिलीटर होनी चाहिए। यदि इस हार्मोन की कमी होती है तो विशेषज्ञ की देखरेख में समय-समय पर ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन देकर खून में इसके स्तर को सामान्य रखने का प्रयास किया जाता है।

निदान व जांच बौनेपन की पहचान बाल्यावस्था में बच्चे के विकास की गति और लक्षणों से की जा सकती है। जब बच्चे की लम्बाई उम्र के अनुसार न होकर बहुत ही धीमी गति से हो तो यह भी बौनेपन का एक लक्षण हो सकता है। वर्तमान में विभिन्न जांचों में मुख्य रूप से खून में ग्रोथ हार्मोन के स्तर की जांच प्रारंभिक अवस्था में करने पर यह तय किया जा सकता है कि कहीं इसकी कमी के कारण बच्चा भविष्य में बौनेपन का शिकार तो नहीं हो जाएगा? यदि रक्त में इसका स्तर सामान्य पाया जाए और यदि बच्चे में वंशानुगत जांच एफजीएफआर-3 जीन में त्रुटि पाई जाए तो बाल्यावस्था में ही बौनेपन की बीमारी को पहचाना जा सकता है। बच्चे के शरीर के सभी जोड़ों के एक्स-रे व एमआरआई से प्रारम्भिक अवस्था में ही बौनेपन की पहचान की जा सकती है। यदि बच्चे की लम्बाई कम है और जांच में कोई बीमारी न मिले तो उसे बौनापन नहीं कहकर छोटे कद का व्यक्ति कहा जाता है।

दूर होगी अनिद्रा की शिकायत

एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया- नींद। जीने के लिए खाना जितना जरूरी है उतनी ही नींद भी। रिसर्च के अनुसार इंसान 12-15 दिन तक बिना खाये रह सकता है लेकिन बिना सोए छः दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। तो ऐसे में नींद की जरूरत को समझा जा सकता है। शहरीकरण का सबसे ज्यादा नुकसान इंसान को अपनी नींद खोकर चुकाना पड़ा है। आज अधिक से अधिक शारीरिक और मानसिक मेहनत कर लेने के बावजूद अनिद्रा की समस्या के मामले बढ़ रहे हैं।

इनसोमनिया डिसऑर्डर: इंसान में कई तरह के स्लीपिंग डिसऑर्डर पाए जाते हैं। उनमें इनसोमनिया डिसऑर्डर सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है। इस बीमारी में मरीज रात को बिस्तर में लेटने के बाद भी जगे रहता है। पूरी कोशिश के बाद भी मरीज को नींद नहीं आती और वह बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलता रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार 18 से 40 वर्ष तक के आयु वाले हर इंसान को 6 घंटे की नींद जरूरी होती है। लेकिन आज देर रात तक जागकर काम करने को लोगों ने क्रिएटिविटी का नाम दिया है। रात तक जागकर काम करने से एक समय के बाद अनिद्रा की शिकायत होना आम समस्या बन जाती है। ऐसे में एक समय के बाद रात को नींद नहीं आती।

4-7-8 ब्रीथिंग ट्रिक: गीता पिछले कई दिनों से रातों को सो नहीं पा रही थी। उसने जब एक सप्ताह रातों को करवटें बदलकर काटे तो उसने विशेषज्ञ से परामर्श लेने के बारे में सोचा। गीता ने जब अपने फैमिली डॉक्टर से इस समस्या के बारे में बताया तो उन्होंने गीता को 4-7-8 ब्रीथिंग ट्रिक की सलाह दी। सबसे आश्चर्य की बात है की ये ट्रिक गीता के लिए फायदेमंद साबित हुई।

ये ट्रिक है क्या?: इस ट्रिक की खोज हार्वर्ड से पढ़े डॉ एंड्रयू वेल ने की, जिन्होंने मेडिटेशन, ब्रिथिंग और तनाव मुक्त करने पर स्टडी की है। यह ट्रिक करने में काफी आसान है और इसे करने में मुश्किल से एक मिनट से भी कम समय लगता है। नाक से चार सकेंड तक के लिए सांस लें, सात सकेंड तक इसे रोक कर रखें, और आठ सकेंड तक इसे छोड़ते रहें। इससे हार्टबीट स्लो होती है और ब्रेन में एक केमीकल रीलिज होता है जिससे हमें आराम मिलता है। जब हम तनाव में होते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनालाइन रीलिज करता है। इससे हार्टबीट बढ़ती है और शरीर में तनाव पैदा होता है। इस ब्रीथिंग ट्रिक के जरिये जो केमीकल रीलिज होता है वो एड्रेनालाइन का काउंटरएक्ट होता है जो हार्टबीट को धीरे करता है। शुरुआत में ये ट्रिक थोड़ी अनकम्फर्टेबल लगती है। लेकिन लगातार उपयोग से आपके शरीर और दिमाग दोनों को आराम मिलता है।

इस तकनीक को आजमाने के बाद भी अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : डॉ. आसमां बेगम ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**